RNI NO.- CHHHIN/2023/87391

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

अंक-11 | वर्ष-3 | माह-फरवरी 2026 | प्रकाशन तिथि- फरवरी 2026 | रायपुर से प्रकाशित | पृष्ठ-40 | मूल्य-11/-

मैनपाट महोत्सव से सरगुजा की संस्कृति को नई पहचान, 23 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात...

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामाजिक समरसता, संवेदनशील शासन और नए भारत की तस्वीर...

जल जीवन मिशन

छत्तीसगढ़

हर घर जल
जल जीवन मिशन

"जल बचाएं,
जीवन खुशहाल बनाएं"

Save water - save life

"स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल का उपयोग करें" | @jjmchhattisgarh

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एक सम्पूर्ण पत्रिका

प्रेरणा स्त्रोतः

जी. स्वामी (रायपुर)

प्रधान संपादकः

जी. भूषण राव

समाचार संपादकः

जी.वी.एस. रूक्मणि देवी

उप संपादकः

राखी श्रीवास्तव

सलाहकार संपादकः

अशोक तोमर

मार्केटिंग हेडः

शैलेन्द्र दवे

मार्केटिंग प्रतिनिधिः

हरिमोहन तिवारी

आवरण सज्जाः

Infinity

ब्यूरो हेडः

बिलासपुरः विनीत चौहान

जशपुरः आनंद गुप्ता

कोरियाः प्रवीण निशी

बस्तरः सुनील सिंह राठौर

आफिसः

बी-13, बसंत पार्क

अनमोल सुपर मार्केट के पास

महावीर नगर, न्यू पुरेना रायपुर छ.ग.

ईमेलः swatantrachhattisgarh@gmail.com

वेबसाईटः www.swatantrachhattisgarh.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

जी. भूषण राव द्वारा सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा मुद्रित एवं बी-13, बसंत पार्क, अनमोल सुपर मार्केट के पास, महावीर नगर, न्यू पुरेना, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

मो.:- 99934-54909

संपादकः जी. भूषण राव

पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखकों के अपने विचार है, किसी भी विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्र रायपुर होगा।

वार्षिक सदस्यता शुल्क सभी (विशेषांकों सहित प्रस्तावित) 132/-रू.मात्र

Pg 05

कोरबा ने रचा इतिहास, 15 हजार से अधिक हस्ताक्षरों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ 'स्वच्छता महासंकल्प 2026...

Pg 06

केंद्रीय बजट 2026-27

विकास, समावेशन और स्थिरता का त्रिस्तरीय रोडमैप

Pg 17

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामाजिक समरसता, संवेदनशील शासन और नए भारत की तस्वीर...

Pg 22

कांग्रेस बनाम ममता- बंगाल की सभी सीटों पर अकेली उतरेगी कांग्रेस, लेकिन किस एजेंडे पर लड़ेगी यह बड़ी लड़ाई?

Pg 31

टी-20, विश्व कप 2026 में भारत का विश्वविजयी अभियान

16 लगातार जीत के साथ रचा नया इतिहास...

छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार और किसान

संतोष, असंतोष और ज़मीनी सच्चाई...

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। राज्य की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि वर्तमान सरकार की नीतियों से किसान कितने संतुष्ट हैं और कहाँ वे असंतोष महसूस कर रहे हैं। वास्तविक तस्वीर एकतरफा नहीं है–कुछ मोर्चों पर राहत और भरोसा दिखता है, तो कुछ मुद्दों पर बेचैनी और अपेक्षाएँ भी स्पष्ट हैं।

राज्य में धान प्रमुख फसल है, इसलिए समर्थन मूल्य और सरकारी खरीदी की व्यवस्था किसानों के लिए सबसे बड़ा कारक है। सरकार द्वारा धान खरीदी की निरंतर व्यवस्था और बोनस जैसी घोषणाओं ने छोटे और सीमांत किसानों को नकदी प्रवाह का भरोसा दिया है। समय पर भुगतान और ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था ने पारदर्शिता बढ़ाई है। कई किसानों का मानना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका कुछ हद तक कम हुई है और उन्हें न्यूनतम मूल्य का आश्वासन मिला है।

इसके अतिरिक्त, कृषि इनपुट पर अनुदान, बीज-वितरण, सिंचाई पंप कनेक्शन और फसल बीमा योजनाओं का विस्तार भी संतोष का कारण बना है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बताते हैं कि सरकारी खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ने से परिवहन लागत कम हुई है। कुछ क्षेत्रों में नहरों और लघु सिंचाई परियोजनाओं के पुनरोद्धार से रबी फसलों का रकबा भी बढ़ा है, जिससे आय में विविधता आई है।

दूसरी ओर, असंतोष के कारण भी कम नहीं हैं। उर्वरक, डीज़ल और मजदूरी लागत में वृद्धि ने खेती की कुल लागत बढ़ा दी है। कई किसानों का कहना है कि रूक्क में वृद्धि वास्तविक लागत वृद्धि की तुलना में पर्याप्त नहीं है। मौसम की अनिश्चितता—अचानक बारिश या सूखा—फसल जोखिम को बढ़ा रही है। फसल बीमा दावों के निपटान में देरी और आकलन प्रक्रिया पर भी सवाल उठते रहे हैं। धान पर अत्यधिक निर्भरता एक संरचनात्मक समस्या के रूप में उभरती है। वैकल्पिक फसलों के लिए बाज़ार और प्रसंस्करण ढांचा अभी भी सीमित है। सब्ज़ी और दलहन उत्पादक किसानों को अक्सर खुले बाज़ार में दाम गिरने की समस्या झेलनी पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में खरीदी केंद्रों पर भीड़, गुणवत्ता जांच में देरी और परिवहन प्रबंधन की चुनौतियाँ किसानों को निराश करती हैं। युवा किसान तकनीकी प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन इकाइयों की कमी को भी एक बाधा मानते हैं।

समग्र रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ के किसान पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हैं और पूरी तरह असंतुष्ट भी नहीं। जिन किसानों को नियमित खरीदी और समय पर भुगतान मिला है, उनमें भरोसा दिखता है; वहीं लागत, मौसम और बाज़ार की अनिश्चितताओं से जूझ रहे किसान अधिक मुखर हैं। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह केवल समर्थन मूल्य पर निर्भर मॉडल से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स को मजबूत करे।

दीर्घकालिक समाधान के लिए सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण, डिजिटल कृषि सेवाएँ और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त करना आवश्यक है। यदि नीति-निर्माण में किसानों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी व समयबद्ध हो, तो संतोष का दायरा बढ़ सकता है। अंततः किसान की खुशी केवल घोषणा से नहीं, बल्कि खेत से मंडी तक की पूरी व्यवस्था की मजबूती से तय होगी।

आपका अपना

भूषण राव

UGC की नई समानता नियमावली

सामाजिक न्याय की दिशा में निर्णायक कदम या क्रियान्वयन की एक और परीक्षा?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026 भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में संस्थागत सुधार का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। 1956 में संसद के अधिनियम के तहत स्थापित UGC का मूल दायित्व विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय और संरक्षण करना रहा है। किंतु बदलते सामाजिक परिदृश्य में केवल अकादमिक उत्कृष्टता पर्याप्त नहीं मानी जा सकती; समानता, समावेशन और गरिमा भी उतने ही आवश्यक तत्व हैं। इसी पृष्ठभूमि में आयोग ने देशभर के परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने हेतु नई नियमावली लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में समान अवसर केंद्र (EOC) और इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। अनुपालन न करने पर डिग्री कार्यक्रम रोकने जैसे कठोर दंड प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

नई नियमावली की पृष्ठभूमि और आवश्यकता

यह विनियम 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित हुआ और यह 2012 से लागू भेदभाव-रोधी नियमों का अद्यतन रूप है। मसौदा संस्करण में OBC को जाति-आधारित भेदभाव की परिधि से बाहर रखने और झूठी शिकायतों पर दंडात्मक प्रावधान जोड़ने को लेकर व्यापक आलोचना हुई थी। शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों ने इसे न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया। अंतिम अधिसूचना में ह्वह्नष्ट को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया और झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रस्ताव हटा दिया गया। 'भेदभाव' की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया ताकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को शामिल किया जा सके। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आयोग ने जनमत और आलोचनाओं को ध्यान में रखा।

हालाँकि, 2012 के विनियमों के कुछ विशिष्ट प्रावधान—जैसे अलग शैक्षणिक प्रणाली पर रोक और प्रवेश प्रक्रिया में SC/ST के खिलाफ आठ प्रकार के भेदभाव का स्पष्ट उल्लेख—अंतिम नियमों में शामिल नहीं किए गए। यह आंशिक अनुपस्थिति कुछ विशेषज्ञों को चिंतित करती है कि कहीं परिभाषात्मक विस्तार के बावजूद प्रवर्तन की स्पष्टता कमजोर न पड़ जाए।

संस्थागत ढांचा- जवाबदेही की नई संरचना

नई नियमावली के तहत प्रत्येक संस्थान में श्वह्नष्ट की स्थापना और उसके अंतर्गत इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य है। इन समितियों में SC, ST, OBC, महिलाओं और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना संस्थागत समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। अर्द्धवार्षिक और वार्षिक रिपोर्टिंग की बाध्यता तथा राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का गठन बहुस्तरीय जवाबदेही तंत्र स्थापित

करता है।

UGC द्वारा डिग्री कार्यक्रम रोकने, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने अथवा सूची से हटाने जैसे दंडात्मक उपायों का प्रावधान नियमों को प्रभावी बनाने का प्रयास है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहाँ हजारों उच्च शिक्षा संस्थान संचालित हैं, इन प्रावधानों के समान और निष्पक्ष अनुप्रयोग की चुनौती भी कम नहीं है।

जनता की प्रतिक्रिया- समर्थन और संशय का मिश्रित भाव

देश में इस नए नियम को लेकर जनमत एकरूप नहीं है। सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के पक्षधर समूह इसे देर से लिया गया लेकिन आवश्यक कदम मानते हैं। उनका तर्क है कि उच्च शिक्षा परिसरों में सूक्ष्म और संरचनात्मक भेदभाव लंबे समय से मौजूद रहा है, जिसके कारण वंचित वर्गों के छात्रों को मानसिक, सामाजिक और अकादमिक दबाव झेलना पड़ता है। उनके अनुसार, स्पष्ट परिभाषाएँ और संस्थागत समितियाँ शिकायत निवारण को औपचारिक और जवाबदेह बनाएंगी। छात्र संगठनों का एक वर्ग भी इसे स्वागतयोग्य मानता है, विशेषकर इसलिए कि अंतिम नियमों में OBC को शामिल किया गया और झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटाया गया। उनका मानना है कि यदि शिकायतकर्ता पर ही दंड का भय रहेगा, तो पीड़ित आगे आने से हिचकेंगे।

दूसरी ओर, कुछ शिक्षाविदों और प्रशासकों में आशंका है कि अत्यधिक नियमन अकादमिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या समितियाँ निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगी, विशेषकर तब जब उनकी अध्यक्षता संस्थान प्रमुख करेंगे। कुछ आलोचक इसे अतिरिक्त नौकरशाही की परत मानते हैं, जो वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय कागजी अनुपालन तक सीमित रह सकती है।

असंतोष के गहरे कारण

UGC के प्रति असंतोष केवल इस नियम तक सीमित नहीं है; यह व्यापक संस्थागत अनुभवों से जुड़ा है। पूर्व में भी भेदभाव-रोधी तंत्र मौजूद थे, परंतु कई मामलों में शिकायतों के निस्तारण में देरी, पारदर्शिता की कमी और संस्थागत उदासीनता के आरोप सामने आते रहे हैं। जनता के एक हिस्से का विश्वास है कि जब तक निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई वास्तविक और समयबद्ध नहीं होगी, तब तक नियम प्रभावी नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में संसाधनों की कमी, संकाय पदों की रिक्तियाँ और क्षेत्रीय असमानताएँ भी असंतोष को बढ़ाती हैं। यदि समावेशन के प्रयास संसाधन-संपन्न संस्थानों तक सीमित रह जाएँ और छोटे या दूरदराज़ के संस्थानों में केवल औपचारिकता बनकर रह जाएँ, तो नियमों का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

क्रियान्वयन- सफलता की कुंजी

किसी भी विनियम की सफलता उसके पाठ में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन में निहित होती है। इक्विटी कमेटियों की नियमित बैठकें, शिकायतों की गोपनीय और निष्पक्ष जांच, और निर्णयों की पारदर्शी रिपोर्टिंग आवश्यक है। साथ ही, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण तथा छात्रों के लिए परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ीकरण भी अनिवार्य है।

जनता का एक बड़ा वर्ग मानता है कि सामाजिक न्याय केवल दंडात्मक प्रावधानों से नहीं, बल्कि संस्थागत संस्कृति में परिवर्तन से संभव है। यदि परिसरों में संवाद, सह-अस्तित्व और विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित नहीं हुई, तो नियम सीमित प्रभाव ही डाल पाएंगे।

अपेक्षाओं और यथार्थ के बीच

UGC की नई समानता नियमावली भारतीय उच्च शिक्षा में सामाजिक समावेशन को संस्थागत रूप देने का गंभीर प्रयास है। जनता में इसके प्रति आशा भी है और संशय भी। आशा इस बात की कि अब भेदभाव के मामलों को औपचारिक रूप से संबोधित किया जाएगा; संशय इस कारण कि क्या यह तंत्र प्रभावी और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा।

अंततः, इस नियम की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि लष्ट और उच्च शिक्षा संस्थान इसे केवल अनुपालन का दस्तावेज न मानें, बल्कि संवैधानिक मूल्यों—समानता, गरिमा और न्याय—को व्यवहार में उतारने का माध्यम बनाएं। यदि क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष रहा, तो यह विनियम भारतीय उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण दिशा में ले जा सकता है; अन्यथा यह भी सुधारों की सूची में एक और अधिसूचना बनकर रह जाएगा।

कोरबा ने रचा इतिहास, 15 हजार से अधिक हस्ताक्षरों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ 'स्वच्छता महासंकल्प 2026

कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता महासंकल्प 2026 के तहत आयोजित ऐतिहासिक जन-जागरूकता अभियान में कोरबा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। एमपी नगर उद्यान, घंटाघर से पंडित रविशंकर शुक्ल नगर मार्ग तक लगाए गए 280 मीटर लंबे एकल बैनर पर एक साथ एक ही समय में 15 हजार से अधिक नागरिकों ने स्वच्छता शपथ पर हस्ताक्षर कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस महाअभियान में शहर के छात्र-छात्राओं, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्य म के दौरान सभी सहभागियों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई और स्वच्छ कोरबा के निर्माण का संकल्प लिया गया। अभियान के अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, सभापति नूतन सिंह, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस सफल आयोजन के लिए महापौर एवं नगर निगम की पूरी टीम को शहरवासियों ने बधाइयां दीं।

इस ऐतिहासिक अभियान में छत्तीसगढ़ अख़बार वितरक संघ की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने नगर निगम के महा संकल्प 2026 के बैनर तले स्वच्छता शपथ पर हस्ताक्षर कर अभियान को मजबूती प्रदान की। संघ ने आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा के एनएसएस जिला संगठक प्रोफेसर वाई.के. तिवारी के नेतृत्व में एनएसएस स्वयंसेवकों मुस्कान राजपूत, देवांश, तुलसी, मैत्री, रूपा, कहकशा, परवीन सहित स्काउट-गाइड जिला के कमिश्नर मोहम्मद सादिक शेख सर, कोरबा ब्लॉक सचिव श्रीमती नमिता श्यामकुंवर कड़वे, शुभम ढिमोले, अनीता खलखो, कोरबा जिले के बच्चे शामिल हुए बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

छत्तीसगढ़ अख़बार वितरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह चंदेल, जिला अध्यक्ष विपेन्द्र कुमार साहू, सचिव जयसिंह नेताम, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी राठौर, सहसचिव रायसिंह, रामा, तपेश्वर राठौर, अनिल गिरी, राजकुमार पटेल, सरोज, हर्ष नेताम, विल्सन, राहुल, विजय सहित बड़ी संख्या में संघ के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता हमारा कर्तव्य है और स्वच्छ कोरबा हमारी पहचान। नागरिकों को विश्वास दिलाया गया कि इसी तरह के निरंतर प्रयासों से कोरबा शहर स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश और देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।

केंद्रीय बजट 2026-27

विकास, समावेशन और स्थिरता का त्रिस्तरीय रोडमैप

कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है-

पहला कर्तव्य

उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल-पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना

दूसरा कर्तव्य

भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना।

तीसरा कर्तव्य

सरकार की सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल- यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत?येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब?ध हो।

बजट अनुमान- गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश 36.5 लाख करोड और 53.5 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड रुपए और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है। गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड रुपए है जिसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियाँ 26.7 लाख करोड रुपए हैं। कुल व?यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड रुपए है जिसका पूंजी व्यय करीब 26.1 लाख करोड रुपए है। बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के बजट में संशोधित राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के समान है। ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी का 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

पहला कर्तव्य

आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना तथा छह हस्त क्षेपों का प्रस्ताव है ,सात रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण, बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्यफ देखभाल को बेहतर करने की रणनीति) की घोषणा।

भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उदेश्य से अगले पांच वर्ष के लिए दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव । तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के निर्माण तथा सात मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क। एक हजार से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया विलनिकल ट्रायल्स स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा। उपकरण और सामग्री बनाने, फुलस्टेक इंडिया आई.पी. डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा।

अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए कलस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर तीन समर्पित कैमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई जाएगी।

पूंजी सामान क्षमता मजबूत करना

डिजिटल रूप से सक्षम ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में दो स्थानों सी.पी.एस.ई. द्वारा हाईटेक टूल रूप स्थापित किए जाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जों का बड़े पैमाने पर और कम लागत से स्थानीय स्तर पर डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत सी.आई.ई. के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना(सी.आई.ई.) शुरू की जाएगी। पांच वर्ष की अवधि में दस हजार करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने प्रस्ताव।

वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा

रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानवनिर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन केन्द्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना।

चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव

खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा।

लीगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना

अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत स्पर्धा और दक्षता में सुधार के लिए दो सौ लीगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव।

चैंपियन एस.एम.ई. बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन

एम.एस.एम.ई. को चैंपियनों के रूप में विकास करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण- दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एस.एम.ई. ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव। दो हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ वर्ष 2021 में बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा। विशेष रूप से टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कार्डर विकसित करने के लिए आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई, आई.सी.एम.ए.आई. जैसे व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन- वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव। समर्पित आर.ई.आई.टी. स्थापित करने के जरिए सी.पी.एस.ई. की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव। पूर्वी भारत में डानकूनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे। जलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोडने के लिए ओडिशा में एनडब्ल्यू-5 से शुरुआत के साथ अगले पांच वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे। अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इनलैंड जलमार्गों और तटीय पोत परिहवन की हिस्सेरदारी 6 प्रतिशत से बढाकर वर्ष 2047 तक 12 प्रतिशत करने के लिए तटीय कार्गो प्रोमोशन स्कीनम आरंभ की जाएगी। सी-प्लेन के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और लास्ट माइल तथा दूरदराज क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संचालन को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए सी-प्लेन वी.जी.एफ. स्कीम शुरू की जाएगी।

दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना

कार्बन टैक्चर उपयोग और भंडारण (सी.सी.यू.एस.) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा।

शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास- शहर आर्थिक क्षेत्र (सी.ई.आर.) के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा। पर्यावरण अनुकूल टिकाउ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए मुम्बई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बैंगलुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बैंगलुरू, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलिगुड़ी के बीच सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि के अगले चरण के साथ कदम-ताल मिलाते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग'' पर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव।पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव।

भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोक्ता अनुकूल रूपरेखा के लिए विदेश मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव। बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करने को प्रोत्साहन करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का सिंगल बॉण्ड जारी करने पर सौ करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव।

दूसरा कर्तव्य

लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता बढ़ाना

विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव। यह फैसला भारत को वर्ष 2047 तक दस प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाएगा।

विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करने

संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशवरों (ए.एच.पी.) के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए ए.एच.पी. संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगले पांच वर्ष में एक लाख ए.एच.पी. जोड़े जाएंगे। वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में डेढ़ लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे

प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने तथा अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने और पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में डब्ल्यू.एच.ओ. वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र के उन्नयन का प्रस्ताव।

पशुपालन- सरकार 20 हजार से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता करेगी। निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव।

ऑरेंज इकोनॉमी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुम्बई को 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और पांच सौ महाविद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब (सी.सी.एल.) स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव।

शिक्षा

सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरीडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगी। वी.जी.एफ./पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी।

पर्यटन

मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव। आई.आई.एम. के सहयोग से हाईब्रिड मोड में मानकीकृत, उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए प्रायोगिक योजना शुरू की जाएगी। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी।

विरासत और संस्कृति पर्यटन

लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अदिचनाल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव।

खेल- अगले दशक में खेल-कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव।

तीसरा कर्तव्य

सबका साथ- सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लिए निम्नशलिखित चार क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है-

किसानों की आय बढ़ाना

किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पांच सौ जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उच्च् मूल्य कृषि

सरकार उच्च् मूल्य वाली फसलों की खेती समर्थन देगी जैसे- तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान की जाएगी। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रो में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए, भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव।

भारत-विस्तार

केन्द्रीय बजट में भारत-विस्तार का प्रस्ताव, जो बहुभाषीय ए.आई. टूल है और जिसे ए.आई. प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए, आई.सी.ए.आर. पैकेज सहित एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता

उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहंस-टू की स्थापना की जाएगी। रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन किया जाएगा।

पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर ध्यान

दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना।

16वां वित्त् आयोग

सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए।

प्रत्यक्ष कर

नया आय कर अधिनियम- नया आय कर अधिनियम, 2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा। सरलीकृत आय कर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि, आम नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके।

जीवन जीने की सुगमता-किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आय कर से छूट दी जाएगी और इस मद में स्त्रोत पर काटा गया कर देय नहीं होगा।

टी.सी.एस. को तार्किक बनाना

विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टी.सी.एस. दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से कम करते हुए दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव। मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत टी.डी.एस. प्रावधानों से श्रम गहन कारोबारियों को लाभ होगा। छोटे करदाताओं के लिए नई योजना का प्रस्ताव, जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से, कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण-पत्र करना संभव हो सकेगा। करदाताओं की सुविधा के लिए डिविडेंट, निवेश से प्रपत्र 15जी अथवा प्रपत्र 15एच स्वीकार करने के लिए सिंगल विंडो। संशोधित रिटर्न के लिए समयसीमा मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई। कर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग-अलग समय सीमा का प्रस्ताव। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टी.डी.एस. की कटौती की जाने और टैन की आवश्यकता के बजाए निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं। छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा के लिए एकमुश्त छह महीने की छूट की योजना। जुर्माने और मुकद्दमेबाजी को तार्किक रूप देना। आई.टी. आकलन और जुर्माने की कार्यवाही को सामान्य रूप से एकीकृत करने का प्रस्ताव है। करदाताओं को अपनी पुनः आकलन कार्यवाही के बाद रिटर्न अपडेट कराने की अनुमति होगी। आय का गलत विवरण देने पर अतिरिक्त आय कर के भुगतान के साथ छूट दी जा सकेगी। आय कर अधिनियम के तहत मुकद्दमेबाजी की रूपरेखा को तार्किक बनाया गया है।

सहकारिता

दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशुचारे और बिनौले की आपूर्ति करने वालों तक भी किया गया है। किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में दिए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव।

भारत के विकास इंजन के रूप में आई.टी. क्षेत्र को सहायता

सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आई.टी. समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाएं 15.5 प्रतिशत के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत आएंगी। आई.टी. सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को तीन सौ करोड़ रुपये बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है। ए.पी.ए. में शामिल होने वाली कम्पनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान की जाएगी।

वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना

किसी ऐसी विदेशी कंपनी के लिए 2047 तक कर मे रियायत दी जाएगी, जो भारत से डाटा केन्द्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक तौर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। यदि, डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी संबंधित कंपनी है तो उसे लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर भी प्रदान किया जाएगा।

कर प्रशासन

भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने के हेतू कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। वर्ष 2027-28 से आय परिकलन और प्रकटन मानकों पर आधारित प्रथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

अन्य् कर प्रस्ताव

बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22 प्रतिशत और गैर-कॉरपोरेट के लिए 30 प्रतिशत होगा। अल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2 प्रतिशत किया जाएगा और तेंदु पत्ते पर 5 प्रतिशत की दर को घटाकर दो प्रतिशत किया जाएगा। वायदा सौदों पर ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी की मौजूदा 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर लगेगा। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए 01 अप्रैल, 2026 से कोई और क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15 प्रतिशत की मौजूदा मैट दर को कम करके 14 प्रतिशत किया जा रहा है।

अप्रत्याक्ष कर- शुल्क सरलीकरण, समुद्री, चमड़ा और वस्त्र उत्पाद

निर्यात हेतु सी-फूड उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इस्तेमाल किए गए विशेष घटकों के कर मुक्त निर्यात की सीमा को एफओबी वैल्यू के मौजूदा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाएगा। चमड़ा अथवा सिंथेटिक फूटवियर के निर्यात के लिए उपलब्ध कर मुक्त निर्यात, उसके विशेष उत्पादों के लिए भी अनुमत होगा।

ऊर्जा संक्रमण एवं सुरक्षा

बैटरियों के लिए लीथियम-आयन सेलों के निर्माण हेतु इस्तेमाल में आने वाली पूंजीगत सामग्रियों के लिए मूलभूत सीमाशुल्क की छूट का विस्तार। सोलर ग्लास के निर्माण में इस्तेमाल हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर मूलभूत सीमाशूल्क से छूट मिलेगी।

न्यूक्लियर पावर- न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूल-भूत सीमा शुल्क का वर्ष 2035 तक विस्तार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण खनिज- महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्रियों के आयात के लिए मूल-भूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी।

बायोगैस मिश्रित सीएनजी- बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की गणना के समय बायोगैस के पूरे मूल्य पर छूट दी जाएगी।

असैनिक एवं रक्षा विमानन

असैनिक, प्रशिक्षण एवं अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी। रक्षा क्षेत्र की ईकाइयों द्वारा रख-रखाव, मरम्मत अथवा अन्य आवश्यकताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

इलैक्ट्रॉनिक्स- माइक्रोवेब ओवन के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पुर्जों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र- विशेष आर्थिक क्षेत्रों से लेकर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पात्र विनिर्माण संयंत्रों द्वारा विक्रय की सुविधा हेतु एक विशेष एकबारगी उपाए का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए रियायती दरों का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे विक्रय की मात्रा उनके निर्यात के निर्धारित अनुपात तक सीमित होगी।

जीवन की सुगमता

व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ दर को 20 प्रतिशत के घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। 17 दवाओं/औषधियों पर मूलभूत सीमाशूल्क में छूट दी जाएगी। अतिरिक्त असाध्य रोगों के लिए दवाओं/औषधियों के व्यक्तिगत निर्यात को कर मुक्त किया जाएगा।

सीमा-शुल्क सरलीकरण प्रक्रिया- वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन में कम से कम हस्तक्षेप

विश्वास आधारित प्रणालियां- एईओ के रूप में परिचित टियर 2 और टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। पात्र विनिर्माणकर्ता और आयातकों के लिए भी समान शुल्क स्थगन सुविधा का प्रस्ताव। सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता

अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया। कार्गो के समाशोधन के लिए अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रमाणन का लाभ लेने के लिए सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन वस्तुओं के आयात के लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा-शुल्क को उनके समाशोधन औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अपने आप सूचना मिल जाएगी। सीमा-शुल्क भंडारण, स्व-प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा।

व्यापार सुगमता

विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और अन्य वन्य जीव उत्पादों, जो निषिद्ध कार्गो का 70 प्रतिशत होता है, के समाशोधन शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक संचालन रूप दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन आवश्यकता नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा-शुल्क एकीकृत प्रणाली 2 वर्षों में शुरु की जाएगी। गैर-सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु एआई प्रौद्योगिकी उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

निर्यात के नए अवसर

विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में माना जाएगा। ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसाय, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यात प्रति खेप 10 लाक रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरफ से हटाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी से जुड़े प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी।सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का समाधान चाहने वाले ईमानदार करदाता अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद कर सकेंगे।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026-27 एक संतुलित और दूरदर्शी दस्तावेज़ है जो तेज विकास, मानव पूंजी निर्माण और व्यापक समावेशन को एक साथ साधने का प्रयास करता है। राजकोषीय अनुशासन, विनिर्माण-नेतृत्व वाला विकास, कर सरलीकरण और व्यापार सुगमता के साथ यह बजट 2047 के विकसित भारत लक्ष्य की ठोस आधारशिला रखता है।

छत्तीसगढ़ के 12 सौ साल पुराने मंदिर में रोज उमड़ती भीड़, अनोखी मान्यता...

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। 9वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर न केवल अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अनूठी स्थापत्य शैली और आध्यात्मिक महत्व के कारण भी विशेष पहचान रखता है। सावन मास में यहां श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। दूर-दूर से भक्त कांवड़ लेकर आते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए यह स्थल आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है।

इस मंदिर का निर्माण बाणवंशीय राजा विक्रमादित्य द्वारा लगभग 870 ईस्वी में प्रारंभ कराया गया था, जिन्हें महामंडलेश्वर मालदेव के पुत्र जयमेयू के नाम से भी जाना जाता था। लगभग 900 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। बाद में 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर का निर्माण युद्ध विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था, जिससे यह केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि शौर्य और वैभव का प्रतीक भी बन गया। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक गरिमा और अधिक सुदृढ़ हुई है।

पाली शिव मंदिर की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका गर्भगृह है। सामान्यत: किसी शिव मंदिर में एक ही शिवलिंग स्थापित होता है, किंतु यहां एक ही गर्भगृह में तीन शिवलिंग स्थापित हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यह अनूठी व्यवस्था इसे अन्य शिवालयों से अलग पहचान देती है। लोककथा के अनुसार प्राचीन समय में युद्ध के दौरान आसपास के दो मंदिर नष्ट हो गए थे, जिसके बाद तीनों शिवलिंगों को सुरक्षित रखकर एक ही स्थान पर स्थापित किया गया। यह कथा मंदिर की रहस्यमयी और आध्यात्मिक आभा को और भी गहरा करती है।

मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसकी मूर्तिकला अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। इसकी कलात्मक शैली राजस्थान के दिलवाड़ा जैन मंदिर तथा मध्यप्रदेश के खजुराहो मंदिर समूह से साम्यता रखती है। अष्टकोणीय मंडप पर ब्रह्मा, श्रीकृष्ण, माता सरस्वती, महिषासुर मर्दिनी और गजलक्ष्मी की सुंदर प्रतिमाएं अंकित हैं। जंघा भाग में नृत्यरत शिव, चामुण्डा, सूर्य और कार्तिकेय के साथ-साथ सामाजिक जीवन के विविध दृश्य भी उकेरे गए हैं, जो उस समय की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इस प्रकार पाली शिव मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि भारतीय कला, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है, जो आज भी श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है।

बोर्ड परीक्षा 2026- विज्ञान विषय में अच्छे अंक कैसे पाएं? जाने विशेषज्ञ माधुरी बोरेकर से...

छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से और कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा नज़दीक आते ही छात्रों में तनाव, भ्रम और तैयारी को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। विज्ञान विषय को लेकर यह चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान—तीनों की अवधारणात्मक समझ, आरेख, समीकरण और आंकिक प्रश्न शामिल होते हैं। इन्हीं सभी पहलुओं पर विज्ञान विषय की विशेषज्ञ शिक्षिका माधुरी बोरेकर ने छात्रों के लिए व्यावहारिक और परीक्षा-उपयोगी सुझाव साझा किए हैं, जो न केवल अंक बढ़ाने में मदद करेंगे बल्कि आत्मविश्वास भी मजबूत करेंगे।

चित्र बनाइए, अंक पाइए- विज्ञान में आरेखों का महत्व

माधुरी बोरेकर के अनुसार, बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में एक आम गलती यह होती है कि छात्र चित्रों (डायग्राम) को हल्के में ले लेते हैं। जबकि सच यह है कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें चित्र बनाकर समझाना अपेक्षित होता है—चाहे प्रश्न में स्पष्ट रूप से चित्र बनाइए लिखा हो या नहीं। विशेषकर चार और पांच अंकों के प्रश्नों में आरेख उत्तर को पूर्णता देते हैं।

वे सलाह देती हैं कि जिन अध्यायों में संरचनाएं, प्रक्रियाएं या नियम आते हैं—जैसे प्रकाश का परावर्तन, मानव हृदय, पादप कोशिका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं—उनके चित्रों की नियमित अभ्यास करें। चित्र जितने साफ, संतुलित और सही नामांकन (लेबलिंग) के साथ होंगे, उतने अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ती है।

नामांकन हिंदी या अंग्रेज़ी—दोनों में किया जा सकता है, लेकिन यदि अंग्रेज़ी में लिखें तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। गलत स्पेलिंग के कारण अंक कट सकते हैं। चित्र बनाते समय बार-बार अभ्यास से हाथ साफ होता है और परीक्षा में समय भी बचता है, वे कहती हैं। कई बार प्रश्न में चित्र बनाने का उल्लेख नहीं होता, लेकिन प्रश्न की प्रकृति ऐसी होती है कि बिना चित्र के उत्तर अधूरा माना जाता है। ऐसे में समझदारी यही है कि छात्र स्वयं पहल करें और चित्र बनाकर उत्तर लिखें।

प्रश्न को समझना है सबसे ज़रूरी- जितना पूछा जाए, उतना ही लिखें

विज्ञान के प्रश्नपत्र में सबसे बड़ी चुनौती प्रश्न को सही ढंग से समझना और उसी अनुरूप उत्तर लिखना है। माधुरी बोरेकर बताती हैं कि कई छात्र अच्छी तैयारी के बावजूद इसलिए अंक खो देते हैं क्योंकि वे प्रश्न से अधिक लिख देते हैं या प्रश्न के सभी हिस्सों को संबोधित नहीं करते।

उदाहरण के तौर पर, यदि प्रश्न दो भागों में है—(अ) और (ब)—तो दोनों का उत्तर देना अनिवार्य है। कई बार छात्र केवल चित्र बना देते हैं और नियम लिखना भूल जाते हैं, या नियम लिखकर चित्र छोड़ देते हैं। जैसे प्रश्न आता है- प्रकाश का परावर्तन क्या है? चित्र बनाकर नियम लिखिए। ऐसे में परिभाषा, साफ चित्र और दोनों नियम—तीनों लिखना आवश्यक है। वे यह भी स्पष्ट करती हैं कि बड़े उत्तरों में अनावश्यक विस्तार से बचें। यदि प्रश्न छोटा है और उत्तर

लंबा लिख दिया गया, तो मूल्यांकनकर्ता अपेक्षित बिंदु न मिलने पर पूरे अंक नहीं देता। इसलिए उत्तर लिखते समय की-वर्ड्स, परिभाषा, सूत्र, चित्र और निष्कर्ष—इनका संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रश्न जितना मांगता है, उत्तर उतना ही दें—यही बोर्ड परीक्षा की सबसे बड़ी रणनीति है, वे कहती हैं।

किन सवालों में होती है सबसे ज़्यादा उलझन?

विज्ञान में कुछ अध्याय और टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो छात्रों को अधिक कठिन लगते हैं। भौतिकी में प्रकाश, चुंबकत्व और विद्युत से जुड़े प्रश्न; रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण और दृक्ष्ट नामकरण; और जीव विज्ञान में अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)—ये सभी सामान्यत: चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। माधुरी बोरेकर के अनुसार, रसायन शास्त्र में समस्या यह होती है कि छात्र समीकरणों को रट लेते हैं, समझते नहीं। परिणामस्वरूप परीक्षा में समीकरण ठीक से नहीं लिख पाते। यदि समीकरणों को अवधारणा के साथ समझा जाए—जैसे अणुभार और परमाणु भार में अंतर—तो न केवल लिखना आसान होता है, बल्कि आंकिक प्रश्न भी सरल लगने लगते हैं। आंकिक प्रश्नों को लेकर वे कहती हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि छात्र को सही सूत्र पता है और यह समझ है कि किस स्थिति में कौन-सा सूत्र लगेगा, तो प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। फार्मूला रटने के बजाय उसके प्रयोग को समझना अधिक लाभकारी है।

पुराने प्रश्नपत्र- सफलता की कुंजी

बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पिछले तीन वर्षों के प्रश्नपत्रों का अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने प्रश्नपत्र देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किन अध्यायों से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की भाषा कैसी होती है और अंक-वितरण कैसे किया जाता है।

माधुरी बोरेकर बताती हैं, पुराने प्रश्नपत्र बच्चों के लिए एक आधार की तरह होते हैं। जब छात्र उन्हें लिख-लिखकर हल करते हैं, तो न केवल लेखन गति बढ़ती है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट और आत्मविश्वास भी सुधरता है। इससे परीक्षा हॉल में घबराहट कम होती है और उत्तर अधिक व्यवस्थित तरीके से लिखे जाते हैं।

रटने से समझ की ओर बढ़ें

अंत में वे एक महत्वपूर्ण बात पर ज़ोर देती हैं—विज्ञान को रटने का विषय न बनाएं। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान—तीनों में यदि छात्र अवधारणाओं को समझ लेते हैं, तो प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे जाएं, उत्तर लिखना आसान हो जाता है। जब समझ विकसित होती है, तो विज्ञान बोझ नहीं रहता, बल्कि एक रोचक विषय बन जाता है, माधुरी बोरेकर कहती हैं। सही रणनीति, नियमित अभ्यास, चित्रों पर पकड़ और प्रश्नों की समझ—इन चार स्तंभों पर टिककर कोई भी छात्र विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष

बोर्ड परीक्षा में सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत का परिणाम है। विज्ञान विषय में यदि छात्र चित्रों का अभ्यास करें, प्रश्नों को समझकर उत्तर दें, पुराने प्रश्नपत्रों से तैयारी करें और रटने के बजाय समझ पर ध्यान दें—तो अच्छे अंक पाना बिल्कुल संभव है। परीक्षा के इस अहम दौर में यही संतुलित और व्यावहारिक तैयारी छात्रों को सफलता की ओर ले जाएगी।

आस्था, संस्कृति और रामकथा से आलोकित हुआ राजिम कुंभ कल्प 2026

छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम की पावन धरा पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। त्रिवेणी संगम के पावन तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सुप्रसिद्ध कलाकार एवं भगवान श्रीराम की भूमिका से जनमानस में विशेष पहचान रखने वाले श्री अरुण गोविल ने ÷सुनो श्री राम कहानी÷ की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण परिसर भक्ति और श्रद्धा के दिव्य वातावरण से ओतप्रोत हो उठा। इस अवसर पर श्री अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आत्मीय भेंट की तथा राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। श्री गोविल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनआस्था और लोगों का आत्मीय स्नेह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आस्था, संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण-संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा ऐसे आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त हो रही है।

कार्यक्रम में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक श्री रोहित साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, संत-महात्माओं एवं श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति थी।

उल्लेखनीय है कि राजिम कुंभ कल्प 2026 के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह महोत्सव आस्था, संस्कृति और पर्यटन संवर्धन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है।

क्या एआई खत्म करेगा रटने की परंपरा और बदलेगा भारत की शिक्षा का चेहरा?

देश में अगले सप्ताह आयोजित होने जा रहा AI Summit India 2026' शिक्षा जगत में एक बड़े परिवर्तन की आहट माना जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की अगुवाई में आयोजित यह समिट केवल एक तकनीकी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक रटने वाली शिक्षा पद्धति को बदलने की एक संगठित पहल के रूप में देखा जा रहा है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) छात्रों में प्रश्न पूछने की आदत विकसित करेगा और उन्हें समझ आधारित शिक्षा की ओर ले जाएगा। 12 फरवरी को देशभर के लगभग 1000 स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इस परिवर्तनकारी पहल की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है।

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि आने वाला समय तकनीक-आधारित शिक्षा का है।द्ध अब केवल एक डिजिटल टूल नहीं रहेगा, बल्कि हर कक्षा का हिस्सा बनेगा। सचिव विनीत जोशी के अनुसार, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी अक्सर परीक्षा के दबाव में विषयों को रट लेते हैं, लेकिन वास्तविक समझ विकसित नहीं कर पाते। AI आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को इंटरैक्टिव तरीके से सीखने का अवसर देंगे, जहां वे बिना झिझक अपने सवाल पूछ सकेंगे। कई बार कक्षा में छात्र इस डर से प्रश्न नहीं पूछते कि कहीं उनका सवाल 'गलत' न समझ लिया जाए, लेकिन AI के साथ यह मनोवैज्ञानिक बाधा समाप्त हो सकती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी लगातार इस बात पर बल देते रहे हैं कि बच्चों को 'रटने' के बजाय 'सोचने और सवाल पूछने' की आदत डालनी चाहिए। AI समिट उसी सोच का विस्तार माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीक को संतुलित और संरचित तरीके से लागू किया गया, तो यह छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमता, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ा सकता है।

AI समिट का दायरा केवल स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मंत्रालय 1000 से अधिक संस्थानों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क विकसित कर रहा है, जहां अकादमिक संस्थान और उद्योग जगत मिलकर नवाचार को बढ़ावा दें। AI आधारित रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। इससे न केवल उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी बढ़ेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि जब कॉलेज, स्टार्टअप और उद्योग एक साझा प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो छात्रों को वास्तविक समस्याओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे वे केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि समाधान विकसित करने की प्रक्रिया को समझेंगे।द्ध आधारित परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार संभव है।

हालांकि AI के कई लाभ हैं, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं छात्र पूरी तरह मशीन पर निर्भर न हो जाएं और अपनी स्वतंत्र सोच खो न दें। विनीत जोशी ने इस आशंका को स्वीकार करते हुए कहा कि AI का उपयोग 'संतुलित' तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शिक्षकों को AI टूल्स के उपयोग, सीमाओं और नैतिक पहलुओं की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि शिक्षक तकनीक को समझेंगे और

सही दिशा देंगे, तभी छात्र इसका रचनात्मक उपयोग कर पाएंगे। साथ ही डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

National Education Policy 2020 (NEP 2020) में पहले ही यह स्पष्ट किया गया था कि भविष्य की शिक्षा बहु-विषयक, लचीली और तकनीक-संलग्न होगी। AI समिट उसी नीति का व्यावहारिक विस्तार है। भारत यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे ज्ञान और तकनीक के समन्वय को प्राथमिकता देनी होगी।

उच्च शिक्षा सचिव का मानना है कि AI के प्रभावी उपयोग से भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकता है। यह समिट केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें शिक्षा को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। यदि यह पहल सफल रही, तो आने वाले वर्षों में भारतीय कक्षाओं का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है—जहां विद्यार्थी रटने के बजाय जिज्ञासा और समझ के आधार पर सीखेंगे।

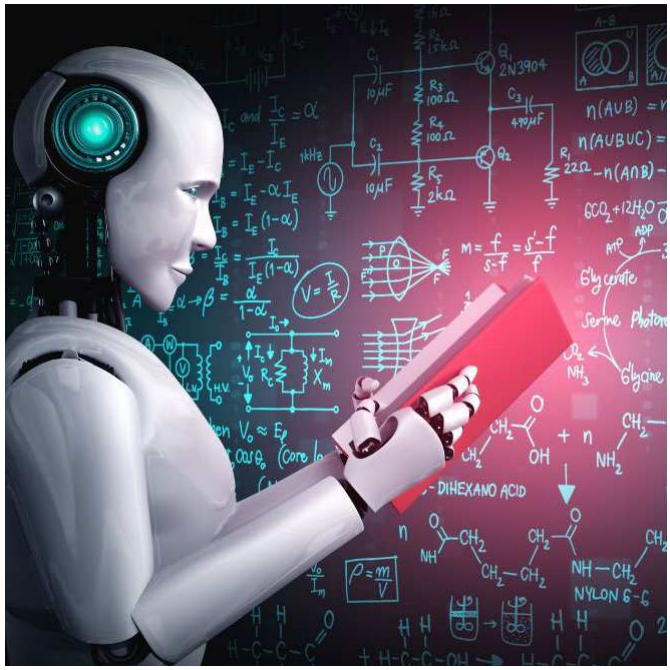

द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड 27 फरवरी 2026 को होगी...

द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड अपने पहले भाग की वैचारिक और भावनात्मक धारा को आगे बढ़ाते हुए कहानी को और व्यापक परिप्रेक्ष्य में ले जाने का प्रयास करती है। फिल्म का ट्रीटमेंट स्पष्ट रूप से अधिक डार्क, गंभीर और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरा हुआ प्रतीत होता है। मोशन पोस्टर और प्रचार सामग्री से संकेत मिलता है कि यह भाग केवल घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि उन सामाजिक और मानवीय परतों की गहराई में उतरने की कोशिश है, जिन्हें अक्सर सतही बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। पटकथा में भावनात्मक तीव्रता और वैचारिक टकराव को संतुलित रखने की चुनौती साफ दिखाई देती है। कमाख्य नारायण सिंह का निर्देशन अपेक्षाकृत संयमित लेकिन प्रभावशाली शैली का संकेत देता है। फ्रेमिंग, बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल टोन फिल्म को एक बेचैन कर देने वाला माहौल देने की कोशिश करते हैं। मनन शाह का संगीत भावनात्मक दृश्यों को गहराई देता है, जबकि गीतों के बोल कहानी के मूड के अनुरूप रखे गए हैं। यदि फिल्म अपने सिनेमैटिक एलिमेंट्स—जैसे एडिटिंग, साउंड डिजाइन और कैरेक्टर बिल्ड-अप—को पहले भाग से अधिक परिपक्व तरीके से प्रस्तुत करती है, तो यह दर्शकों पर लंबा प्रभाव छोड़ सकती है।

उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा जैसे कलाकारों के कंधों पर इस बार भावनात्मक भार अधिक दिखाई देता है। फिल्म की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कलाकार अपने किरदारों की आंतरिक पीड़ा और संघर्ष को कितनी विश्वसनीयता से स्क्रीन पर उतार पाते हैं। कुल मिलाकर, द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड एक ऐसी फिल्म लगती है जो केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बहस और विचार को जन्म देने का लक्ष्य रखती है। यदि कहानी और प्रस्तुति में संतुलन बना रहता है, तो यह सीक्वल भी दर्शकों के बीच मजबूत चर्चा का विषय बन सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

सामाजिक समरसता, संवेदनशील शासन और नए भारत की तस्वीर...

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 10 फरवरी 2026 को जो दृश्य साकार हुआ, वह केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं था, बल्कि सामाजिक चेतना, समरसता और संवेदनशील शासन का जीवंत प्रतीक था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक ही दिन में 6,412 जोड़ों का विवाह और उसका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना, यह स्पष्ट करता है कि जब शासन की नीतियों में मानवीय दृष्टि जुड़ती है, तब योजनाएं आंकड़ों से आगे बढ़कर जीवन बदलने का माध्यम बन जाती हैं। यह आयोजन साबित करता है कि सामाजिक कल्याण केवल बजट और घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा विषय है।

भारतीय समाज में बेटी का विवाह लंबे समय तक एक आर्थिक और मानसिक चुनौती के रूप में देखा जाता रहा है, विशेषकर गरीब और वंचित परिवारों के लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है। 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता केवल राशि नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को दिया है। इससे एक ओर अनावश्यक कर्ज और सामाजिक दबाव कम होता है, वहीं दूसरी ओर बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर भी प्रभावी रोक लगती है। सामूहिक विवाह का स्वरूप दिखाता है कि सरकार विवाह को दिखावे और प्रतिस्पर्धा से निकालकर सादगी, सम्मान और समानता के मंच पर लाना चाहती है।

इस आयोजन का सबसे सशक्त पक्ष इसकी सामाजिक समरसता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और बैगा जनजाति सहित विभिन्न समुदायों के जोड़ों का एक ही मंच पर, अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार विवाह होना, छत्तीसगढ़ की साझा संस्कृति की मजबूत तस्वीर पेश करता है। यह उस दौर में विशेष महत्व रखता है, जब समाज में कई बार विभाजन की रेखाएं गहरी होती दिखती हैं। मुख्यमंत्री का यह कहना कि यह केवल विवाह नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव का उत्सव है, अपने आप में शासन की वैचारिक दिशा को स्पष्ट करता है। यह आयोजन संदेश देता है कि विविधता भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

विश्व रिकॉर्ड का दर्ज होना इस कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय पहचान जरूर देता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इसका सामाजिक प्रभाव है। जब हजारों परिवार एक साथ सम्मान के साथ अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, तो समाज में एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। यह भावना मजबूत होती है कि सरकार केवल योजनाएं बनाने वाली संस्था नहीं, बल्कि संकट और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाला भरोसेमंद सहयोगी है। यही विश्वास लोकतंत्र की असली नींव होता है।

इसी मंच से कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत होना भी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। विवाह जैसे सामाजिक आयोजन को स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ना यह दर्शाता है कि सरकार सामाजिक विकास को समग्र दृष्टि से देख रही है। सरगुजा और बस्तर संभाग के आठ जिलों से शुरू हुआ यह पायलट प्रोजेक्ट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कुपोषण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज की भागीदारी से ही खत्म किया जा सकता है। यदि यह अभियान सफल होता है और पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा।

को साथ लेकर चलने की है। यह संतुलन ही विकास को टिकाऊ बनाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के वक्तव्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि यह योजना किसी एक सरकार या व्यक्ति की नहीं, बल्कि निरंतरता और साझा प्रयास का परिणाम है।

सम्पादकीय दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का मॉडल है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह योजना आने वाले वर्षों में भी पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय संवेदनशीलता के साथ लागू होती रहे। यदि ऐसा हुआ, तो यह पहल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकती है। अंततः, विकास वही सार्थक है जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान ला सके—और इस आयोजन ने उसी दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री द्वारा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं—महतारी वंदन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में निर्णय, चरण पादुका योजना, श्रीरामलला दर्शन योजना और भूमिहीन मजदूरों को सहायता—का उल्लेख यह दिखाता है कि शासन की प्राथमिकता समाज के विभिन्न वर्गों

मैनपाट महोत्सव से सरगुजा की संस्कृति को नई पहचान, 523 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात...

मैनपाट में आयोजित तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह महोत्सव सरगुजा की संस्कृति, अस्मिता और पारंपरिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने मैनपाट में पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ रुपये तथा सीतापुर में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की। समारोह में तिब्बती समुदाय द्वारा ताशी शोपा नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली।

मुख्यमंत्री ने जिले में 523 करोड़ 20 लाख 53 हजार रुपये के 109 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 429 करोड़ से अधिक की लागत के 81 कार्यों का भूमिपूजन और 94 करोड़ से अधिक की लागत के 28 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और केंद्र की सबका साथ, सबका विकास नीति को धरातल पर उतार रही है। महतारी वंदन योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मैनपाट जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र में पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और हितग्राहियों को सामग्री वितरित की गई। जनप्रतिनिधियों ने इसे जन-गौरव का उत्सव बताते हुए विश्वास जताया कि इन विकास कार्यों से आधारभूत संरचना मजबूत होगी और सरगुजा क्षेत्र को नई आर्थिक गति मिलेगी।

आरक्षण पर नई बहस
सामाजिक न्याय, आर्थिक यथार्थ और संविधान का संतुलन

राखी श्रीवास्तव

भारत में आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में है। सवाल उठ रहे हैं–क्या आरक्षण का आधार केवल जाति होना चाहिए? क्या आर्थिक रूप से कमजोर हर नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए? क्या जिन परिवारों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उन्हें आगे इससे वंचित कर देना चाहिए? ये प्रश्न भावनात्मक अवश्य हैं, पर इनका उत्तर संवैधानिक ढांचे और सामाजिक वास्तविकताओं के संतुलन में ही खोजा जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आरक्षण की मूल अवधारणा गरीबी उन्मूलन की योजना के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के औजार के रूप में सामने आई थी। सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता और अवसरों से वंचित रहने की स्थिति ने कुछ समुदायों को मुख्यधारा से दूर रखा। संविधान निर्माताओं ने इसे केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि संरचनात्मक सामाजिक बहिष्कार माना। इसीलिए अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जैसे प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था समानता के विरुद्ध नहीं, बल्कि समानता की स्थापना के लिए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि वास्तविक समानता के लिए विशेष प्रावधान आवश्यक हो सकते हैं।

आर्थिक आधार की बढ़ती मांग

समय के साथ यह तर्क मजबूत हुआ है कि आज की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक असमानता है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आते हैं जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, चाहे वे किसी भी जाति के हों, संसाधनों और अवसरों की कमी से जूझते हैं। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10त्न आरक्षण की व्यवस्था इसी सोच का परिणाम थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक मान्यता भी दी। यह संकेत है कि संविधान की व्याख्या समय के साथ सामाजिक-आर्थिक बदलावों के अनुरूप विकसित हो सकती है।

फिर भी, यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या केवल आर्थिक आधार पर्याप्त है? सामाजिक भेदभाव और आर्थिक गरीबी समानार्थी नहीं हैं। कई बार सामाजिक पहचान स्वयं एक अवरोध बन जाती है, भले ही व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न क्यों न हो।

एक बार लाभ, फिर समाप्ति- क्या यह संभव है?

यह विचार भी सामने आता है कि यदि किसी परिवार का सदस्य आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवा में आ चुका है, तो अगली पीढ़ी को यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। OBC वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा इसी दिशा में एक कदम है, जहां एक निश्चित आय सीमा से ऊपर के परिवारों को आरक्षण से बाहर रखा जाता है। परंतु SC/ST वर्ग के संदर्भ में न्यायालय ने अब तक यह माना है कि सामाजिक भेदभाव केवल आय से समाप्त नहीं हो जाता। यदि ÷एक बार लाभ मिलने पर स्थायी वंचना÷ जैसा नियम बनाया जाए, तो यह व्यापक संवैधानिक परीक्षण से गुजरेगा। यह सिद्ध करना होगा कि सामाजिक पिछड़ापन एक पीढ़ी में समाप्त हो जाता है–जो वर्तमान सामाजिक यथार्थ से मेल नहीं खाता।

मूल प्रश्न- सुधार या पुनर्परिभाषा?

आज की बहस का सार यह नहीं कि आरक्षण रहे या समाप्त हो, बल्कि यह है कि उसे अधिक न्यायसंगत और प्रभावी कैसे बनाया जाए। क्या डेटा-आधारित समीक्षा की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए? क्या क्रीमी लेयर की अवधारणा को और पारदर्शी बनाया जाए? क्या सामाजिक और आर्थिक दोनों मानकों का संतुलित मॉडल विकसित किया जाए?

इन प्रश्नों पर गंभीर नीति-स्तरीय विचार की आवश्यकता है, न कि केवल भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की।

संवाद की आवश्यकता

आरक्षण भारत की सामाजिक संरचना से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। इसे केवल जाति बनाम आर्थिक आधार की बहस में सीमित करना पर्याप्त नहीं होगा। संविधान ने सामाजिक न्याय, समान अवसर और लोकतांत्रिक संतुलन–तीनों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विमर्श तथ्य, डेटा और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़े। सुधार संभव हैं, पर वे ऐसे हों जो समाज को विभाजित करने के बजाय अवसरों की वास्तविक समानता को मजबूत करें। आरक्षण पर बहस जारी रहेगी, पर अंतिम कसौटी यही होगी–क्या नीति समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सम्मान और अवसर दिलाने में सक्षम है?

हार्ट अटैक से बचने के लिए कितनी देर और कितने कदम चलना चाहिए?

आज की दुनिया में, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि खुद को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खाने में मिलावट, खराब मौसम, प्रदूषण और कई दूसरे कारण बीमारियों की वजह बनते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट और डॉक्टर मानते हैं कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको हेल्दी रहने और लंबी जिंदगी जीने में मदद कर सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉकिंग यानी पैदल चलने की...क्टरों का कहना है कि सिर्फ इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए कितना चलना चाहिए? तो, आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी देर और कितने कदम चलना चाहिए।

वॉकिंग के फायदे

चलना एक आसान और असरदार एक्टिविटी है जिसके कई फायदे हैं, जिसमें दिल की सेहत में सुधार भी शामिल है. यह दिल को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, वजन कम करने में मदद करता है, और तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कम होता है।

हार्ट अटैक से बचने के लिए कितना चलना चाहिए?

अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए, हर दिन कम से कम 30 मिनट (हफ्ते में 5 दिन) तेज चलना (लगभग 9000 से 10,000 कदम) एक बहुत अच्छा लक्ष्य है, क्योंकि इससे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद मिलती है. हालांकि, अगर आप इतना नहीं चल पाते हैं, तो कम कदमों से शुरू करने पर भी (जैसे 3,800-4,000) सेहत को फायदे मिलते हैं. जरूरी बात यह है कि आप रेगुलर एक्टिव रहें और तेज गति बनाए रखें. सबसे जरूरी बात, चलते समय आपको इतनी तेज चलना चाहिए कि आपकी सांस थोड़ी फूल जाए लेकिन आप फिर भी बात कर सकें, और धीरे-धीरे अपनी स्पीड और समय बढ़ाएं. हमेशा वार्म-अप और कूल-डाउन करना याद रखें।

अध्ययन का क्या है कहना?

2023 की नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग रोजाना 6,000 से 9,000 कदम चलते हैं, उन्हें दिल की बीमारियों, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा उन लोगों की तुलना में 40 फीसदी से 50 फीसदी कम होता है, जो रोजाना सिर्फ 2,000 कदम चलते हैं. हालांकि हर इंसान के कदम की दूरी अलग-अलग होती है. यहां 6,000 कदम चलने का मतलब लगभग 2.5 मील और 9,000 कदम का मतलब 4 मील से थोड़ा ज्यादा होता है।

इस स्टडी में आठ अलग-अलग स्टडीज से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के 20,152 लोग शामिल थे. हर पार्टिसिपेंट ने अपने स्टेप काउंट को ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस पहना था, और रिसर्चर्स ने छह साल तक पार्टिसिपेंट्स की हेल्थ पर नजर रखी. कुल मिलाकर, इस स्टडी में पाया गया कि किसी भी तरह से चलना, चाहे तेज चलना हो या धीरे-धीरे टहलना, बुजुर्गों में दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा कम कर सकता है। इस स्टडी में युवा वयस्कों में स्टेप काउंट और दिल की बीमारी के खतरे के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं पाया गया. हालांकि, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी पूरी सेहत और भलाई के लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है।

फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी फीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट की वाइस चेयर और इस स्टडी की को-ऑथर डॉ. मर्सिडीज कार्नेथॉन, PhD का कहना है कि यह उन बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है जो हर दिन 10,000 कदम नहीं चल पाते हैं. दूसरे शब्दों में, यह स्टडी उन बुजुर्गों के लिए उत्साहजनक है जो 10,000 कदम नहीं चल पाते हैं, क्योंकि 6,000-9,000 कदम भी कार्डियोवैस्कुलर सेहत के लिए काफी फायदे देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी न करने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है।

ज्यादा कदम कैसे चलें

शुरुआत करने के लिए- जब भी मौका मिले, बिना रुके चलें. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप धीरे चलते हैं या तेज, बस चलते रहें, क्योंकि हर कदम मायने रखता है. आप अपनी रोज की दिनचर्या में और कदम जोड़ने के लिए कुछ छोटी-छोटी चीजें भी कर सकते हैं...

सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।
अपने लंच ब्रेक के दौरान टहलें।
पार्किंग लॉट के पीछे गाड़ी पार्क करें।
टीवी कमर्शियल ब्रेक के दौरान घूमें।
टहलने के लिए कोई साथी ढूंढें।
अपने आने-जाने में टहलने को शामिल करें।
ज्यादा चलने के अलावा, हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है।
अच्छे दिल की सेहत के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है।

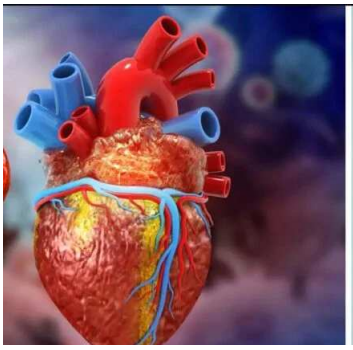

कर्ज, कानूनी लड़ाई और इंसानी संवेदना- राजपाल यादव की मुश्किल घड़ी में सोनू सूद का साथ...बोले ये चेरिटी नहीं सम्मान है

- 2010 के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर
- 5 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में भावुक हुए अभिनेता
- सोनू सूद ने सार्वजनिक रूप से समर्थन देते हुए इंडस्ट्री से एकजुट होने की अपील की
- कानूनी संकट और मानवीय संवेदना के बीच बॉलीवुड की प्रतिक्रिया

साल 2010 से जुड़े एक पुराने चेक बाउंस मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को अंततः दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। करीब 5 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान न कर पाने के कारण यह स्थिति बनी। सरेंडर से ठीक पहले उनका भावुक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और इस कठिन परिस्थिति से उन्हें अकेले ही गुजरना होगा। यह दृश्य केवल एक कानूनी कार्रवाई भर नहीं था, बल्कि एक ऐसे कलाकार की पीड़ा भी थी जिसने वर्षों तक दर्शकों को हंसाया और अपनी अदाकारी से पहचान बनाई। यह मामला एक बार फिर इस प्रश्न को सामने लाता है कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे आर्थिक और कानूनी संघर्ष कितने जटिल हो सकते हैं। ऐसे समय में अभिनेता सोनू सूद ने राजपाल यादव के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजपाल यादव एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जिन्होंने लंबे समय तक इंडस्ट्री को यादगार भूमिकाएं दी हैं। उनके अनुसार, जीवन में कभी-कभी परिस्थितियां व्यक्ति के टैलेंट के कारण नहीं, बल्कि खराब समय के कारण कठिन हो जाती हैं। सोनू सूद ने यह भी स्पष्ट किया कि राजपाल उनकी आगामी फिल्म का हिस्सा होंगे और यह समय इंडस्ट्री के निर्माताओं, निर्देशकों और सहयोगियों के लिए एकजुट होने का है। उनका यह बयान न केवल व्यक्तिगत समर्थन है, बल्कि फिल्म उद्योग में पेशेवर एकजुटता और मानवीय सहयोग का संदेश भी देता है। राजपाल यादव का मामला यह दर्शाता है कि मनोरंजन जगत में सफलता और संघर्ष साथ-साथ चलते हैं। आर्थिक विवाद और कानूनी प्रक्रियाएं किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध क्यों न हो। साथ ही, सोनू सूद की पहल यह संकेत देती है कि कठिन समय में सहकर्मियों का साथ किसी भी कलाकार के लिए मनोबल का स्रोत बन सकता है। यह प्रकरण केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, पेशेवर जिम्मेदारी और उद्योग की सामाजिक भूमिका पर भी चर्चा का अवसर है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या फिल्म इंडस्ट्री वास्तव में अपने कलाकारों के लिए एक सहायक तंत्र के रूप में सामने आती है।

कांग्रेस बनाम ममता- बंगाल की सभी सीटों पर अकेली उतरेगी कांग्रेस, लेकिन किस एजेंडे पर लड़ेगी यह बड़ी लड़ाई?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। सवाल यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे, किस रणनीति और किस राजनीतिक लक्ष्य के साथ बंगाल की जनता के बीच जाएगी

पश्चिम बंगाल में अप्रैलङ्कमई के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तेजी से गर्म होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह साफ कर दिए जाने के बाद कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी दल के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, राज्य की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। ममता के इस फैसले ने न केवल विपक्षी दलों की रणनीति को प्रभावित किया है, बल्कि कांग्रेस को भी एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर किया। कांग्रेस नेतृत्व ने अब यह तय कर लिया है कि पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों।

कांग्रेस का यह निर्णय कई मायनों में अहम है। एक ओर इसे पार्टी की मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने सहयोग की संभावना पूरी तरह खत्म कर दी है। दूसरी ओर, कांग्रेस इसे अपनी राजनीतिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र पहचान की कोशिश के रूप में भी पेश कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस बंगाल में अपने बलबूते जनता के बीच जाएगी और राज्य की समस्याओं पर सीधी लड़ाई लड़ेगी। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस का संगठन बंगाल में कमजोर पड़ा है और उसका जनाधार सीमित होता गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में कांग्रेस की भूमिका कुछ हद तक वैसी ही हो सकती है जैसी दिल्ली और बिहार के चुनावों में देखने को मिली थी। वहां कांग्रेस ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्य मुकाबला अन्य दलों के बीच ही सिमट कर रह गया। बंगाल में भी आशंका जताई जा रही है कि चुनावी लड़ाई का केंद्र तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगा, जबकि कांग्रेस एक सीमित प्रभाव वाली तीसरी शक्ति के रूप में सामने आ सकती है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पार्टी को अपनी प्रासंगिकता साबित करनी होगी।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस बंगाल में किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी के संभावित चुनावी मुद्दों में बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव, संघीय ढांचे की मजबूती और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को भी जोर-शोर से उठाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, चुनौती यह

है कि क्या ये मुद्दे ममता बनर्जी की लोकलुभावन योजनाओं और तृणमूल की मजबूत संगठनात्मक पकड़ के सामने जनता को प्रभावित कर पाएंगे।

ममता बनर्जी पिछले एक दशक से अधिक समय से बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत धुरी बनी हुई हैं। उनकी छवि एक जमीनी नेता की है और तृणमूल कांग्रेस का कैडर गांव-गांव तक फैला हुआ है। इसके मुकाबले कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर कमजोर दिखाई देती है। कई वरिष्ठ नेता या तो निष्क्रिय हैं या अन्य दलों में जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वह न केवल चुनाव लड़े, बल्कि प्रभावी तरीके से प्रचार भी करे और मतदाताओं को यह विश्वास दिला सके कि वह एक व्यवहारिक विकल्प है।

यह चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सीटें जीतने का नहीं, बल्कि राजनीतिक साख बचाने और पुनर्निर्माण का भी अवसर है। अगर पार्टी सम्मानजनक प्रदर्शन करने में सफल रहती है, तो यह उसके लिए भविष्य की राजनीति की नींव रख सकता है। लेकिन यदि नतीजे बेहद कमजोर रहते हैं, तो कांग्रेस की भूमिका बंगाल में और सीमित हो सकती है। पार्टी नेतृत्व के लिए यह जरूरी होगा कि वह स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखकर रणनीति बनाए।

आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि बंगाल की लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी या फिर तृणमूल और भाजपा के बीच ही सिमट जाएगी। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सियासी गणित को जरूर प्रभावित करेगा, लेकिन इसका अंतिम असर मतदाताओं के रुझान पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बंगाल की राजनीति में मुकाबला और तीखा, और अधिक दिलचस्प हो गया है।

RBI New Rules: बिना जरूरत थमाए गए बैंक प्रोडक्ट पर अब मिलेगा पूरा रिफंड, ग्राहकों को बड़ी राहत

अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बैंक कर्मचारियों ने टारगेट पूरा करने के दबाव में आपको बिना जरूरत बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड, लोन टॉप-अप या निवेश प्रोडक्ट थमा दिया हो, तो अब राहत की खबर है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तरह की मिस-सेलिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। ये नियम "RBI

(Commercial Banks–Responsible Business Conduct) Amendment Direction, 2026 के तहत 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।

नए मसौदे के अनुसार, यदि कोई बैंक ग्राहक को गलत तरीके से कोई वित्तीय उत्पाद या सेवा बेचता है, तो बैंक को न सिर्फ पूरी राशि वापस करनी होगी बल्कि ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। आरबीआई ने इन ड्राफ्ट नियमों पर 4 मार्च तक जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कदम बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

ड्राफ्ट नियमों में साफ कहा गया है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान किसी भी उत्पाद का विज्ञापन, मार्केटिंग या बिक्री करते समय पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी बरतेंगे। ग्राहक से संपर्क करने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति जरूरी होगी और कॉल या संपर्क केवल कार्यालय समय में ही किया जा सकेगा। इसके अलावा, बैंकों की आंतरिक नीतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कर्मचारियों या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को गलत बिक्री के लिए प्रेरित करें। यानी इंसेंटिव सिस्टम सिर्फ बिक्री बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ग्राहक के हित पर आधारित होना चाहिए।

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी बैंक को अपने उत्पाद के साथ किसी थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट को जबरन जोड़ने (टाई-इन सेल) की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक को अलग-अलग कंपनियों के विकल्पों में से स्वतंत्र रूप से चयन करने का अधिकार मिलेगा। कुल मिलाकर, इन नए नियमों का मतलब साफ है–अब बैंक झूठ या दबाव के जरिए कोई स्कीम या पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

यमुना किनारे कश्मीर की झलक.....

दिल्ली अब अपनी पहचान को केवल ऐतिहासिक धरोहरों, चौड़ी सड़कों और आधुनिक इमारतों तक सीमित नहीं रखना चाहती। बदलते समय के साथ राजधानी की सोच भी बदल रही है, जिसमें शहरी विकास के साथ-साथ प्रकृति, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी दृष्टिकोण के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित बांसेरा पार्क के पास एक अनोखी पर्यटन परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत यहां पारंपरिक कश्मीरी शैली की हाउसबोट विकसित की जाएगी, जो दिल्ली में पर्यटन और सांस्कृतिक अनुभव को एक नया आयाम देगी।

इस हाउसबोट पर लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह हाउसबोट वास्तविक जल में तैरने वाली नाव नहीं होगी, बल्कि जमीन पर स्थायी रूप से बनाई जाएगी। इसके बावजूद इसका स्वरूप और डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि यह कश्मीर की डल झील में तैरने वाली पारंपरिक हाउसबोट का आभास कराए। दिल्ली विकास प्राधिकरण का मानना है कि मजबूत कंक्रीट नींव और आधुनिक निर्माण तकनीकों के कारण यह संरचना आने वाले कम से कम 50 वर्षों तक सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहेगी। इस परियोजना का उद्देश्य केवल एक नई इमारत खड़ी करना नहीं है, बल्कि यमुना किनारे के क्षेत्र को एक जीवंत पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। बांसेरा पार्क पहले ही दिल्ली के प्रमुख हरित स्थलों में अपनी पहचान बना चुका है। यमुना किनारे फैला यह पार्क हरियाली, खुले मैदानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। यहां समय-समय पर सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम और पारिवारिक गतिविधियां होती रही हैं। दिसंबर 2025 में पार्क में स्थापित बंधे हुए हॉट एयर बैलून ने इसे और अधिक आकर्षक बना दिया, जिससे लोग ऊंचाई से यमुना और आसपास के इलाके का दृश्य देख सकते हैं। अब प्रस्तावित हाउसबोट इस पार्क की पहचान को और सशक्त करेगी और इसे राजधानी के विशिष्ट पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करेगी। हाउसबोट को पूरी तरह पारंपरिक कश्मीरी शैली में निर्मित किया जाएगा। इसके निर्माण में देवदार, सीडर, अखरोट और चिनार जैसी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ियों का उपयोग होगा। रेलिंग, खंभे, मेहराबदार दरवाजे और बाहरी दीवारों पर फारसी शैली की बारीक नक्काशी की जाएगी, जिससे इसे शाही और कलात्मक रूप मिलेगा। अंदर की संरचना में मल्टीपर्पज हॉल, लॉबी, पैंट्री, भोजन के लिए अलग स्थान, आगे-पीछे खुले डेक, शीशे से घिरा मीटिंग हॉल, बालकनी और स्टोरेज एरिया जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह हाउसबोट रहने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और कॉर्पोरेट आयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

सुरक्षा और मजबूती को परियोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। निर्माण से पहले सभी लकड़ियों को अच्छी तरह सुखाया जाएगा, जोड़ों को प्राकृतिक रेजिन से सील किया जाएगा और लकड़ी की सतहों पर अग्निरोधक पेंट की परतें चढ़ाई जाएंगी। दीवारों और दरवाजों में फायर रेजिस्टेंट सामग्री का उपयोग होगा। ष्ठष्ठ ने इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और चयनित एजेंसी को छह महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा। यह हाउसबोट न केवल दिल्ली के शहरी पर्यटन को नई दिशा देगी, बल्कि यह राजधानी की उस बदलती सोच का प्रतीक भी बनेगी, जिसमें विकास के साथ-साथ प्रकृति, कला और संस्कृति को समान महत्व दिया जा रहा है।

सुशासन से समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़

विष्णु के सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़

छगन लोन्हारे
उप संचालक (जनसंपर्क)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढ़कर राज्य के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। इस दृष्टि से आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले वे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश मे हाल ही में पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षको का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह शामिल हुए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खाते में 52 हजार करोड़ रुपए अंतरित कर उन्हें उत्साह से भर दिया है। धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया है। 52 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में आने से वे खेती किसानी में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकार्ड आंकड़ा छू लिया है। धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई और गत वर्ष 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान बेचा। सरकार बनने के दूसरे दिन ही केबिनेट की बैठक कर मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

विष्णुदेव साय ने अपने दो साल के संक्षिप्त कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को सम्पूर्ण देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। बहुत कम समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है और न केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल विष्णुदेव साय जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं। नक्सल हिंसा प्रभावित गांवों में नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच रही है। प्रदेश में अब तक कुल 69 सुरक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते ही प्रदेश की समस्त महिलाओं को महतारी वंदन योजना जैसी एक लाभकारी योजना का सौगात दिया है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए की राशि दी जाती है जिससे वे स्वावलंबी बन सके एवं स्वयं का रोजगार भी प्रारंभ कर सके। साथ ही प्रदेश भर के किसानों को 2 साल का बकाया बोनस और 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जैसे वादों को पूरा कर छत्तीसगढ़ के किसानों का मान बढ़ाया है। प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7.69 लाख रूपए के निवेश के प्रस्ताव मिले

हैं।

खरीफ सीजन में उपज का वाजिब कीमत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान का उपार्जन किया गया। सरकार किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की है। मुख्यमंत्री श्री साय की नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से किसानों के खाते में 52 हजार करोड़ रूपए की राशि अंतरित (ट्रांसफर) हुई है। प्रदेश के नगर पालिका चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त हुआ। प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार से नगरों का सर्वांगीण विकास होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों के अदम्य साहस और सरकार के निरंतर प्रयासों से नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमितशाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। वो संकल्प पूरा होते साफ दिख रहा है विशेषकर बस्तर क्षेत्र में, जो वर्षों से विकास की मुख्यधारा से अछूता रहा है। वहां अब विकास की गंगा बहेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में बीते 02 वर्षों में 529 नक्सली मारे जा चुके हैं, 1975 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 2628 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रदेश के बस्तर अंचल में आतंक का पर्याय रहे हार्डकोर नक्सली लीडर बसवराजू, लक्ष्मी नरसिम्हा चालम उर्फ सुधाकर, और माडवी हिड़मा को न्यूट्रलाइज किया गया इन पर करोड़ों का ईनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सके और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सके। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय पद्रेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जिनके लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके अपने बीच के लोकप्रिय नेता हैं जिनके लिए प्रदेश की जनता की खुशहाली ही सर्वोपरि है।

रियल एस्टेट को राहत- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से CREWA प्रतिनिधिमंडल की सौजन्य मुलाकात...

राज्य सरकार द्वारा जमीन की गाइडलाइन दरों के पुनर्मूल्यांकन और रियायत के निर्णय पर रियल एस्टेट क्षेत्र ने जताया आभार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी की उम्मीद।

रायपुर में औपचारिक भेंट और सम्मान- रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा जमीन की गाइडलाइन दरों का पुनर्मूल्यांकन कर रियायत प्रदान करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को गजमाला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया, जिससे बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा।

रियल एस्टेट और आम नागरिकों को लाभ- एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि गाइडलाइन दरों में रियायत से रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति मिलेगी और परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा। उनका मानना है कि इससे मकान खरीदने वाले आम नागरिकों को भी सीधी राहत मिलेगी, साथ ही निर्माण गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रतिनिधिमंडल ने इसे उद्योग और उपभोक्ता—दोनों के हित में लिया गया संतुलित कदम बताया।

सरकार की प्रतिबद्धता और आर्थिक विकास- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि गाइडलाइन दरों में संशोधन करते समय किसानों, व्यवसायियों और आम नागरिकों—सभी वर्गों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई गाइडलाइन दरें राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देंगी और विकास को प्रोत्साहित करेंगी। बैठक में ष्ट्रक्रश्वङ्ख अध्यक्ष महेंद्र आहूजा सहित दीपक रहेजा, राजीव अग्रवाल, विजय पिंजानी, अजय अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, मुलकराज शर्मा, रजत चाबड़ा, विलास सुतार, विनोद छितिजा, विजय मोटवानी, सनी सेवलानी और गौरव खेतपाल उपस्थित रहे।

21 वर्षों बाद अपने ही विद्यालय में प्रस्तुति दिए इंडियन आयडल बहने...

आज के समय में जब आधुनिक जीवनशैली के दबाव में पारंपरिक पर्व और सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे में मकर सं ांति जैसे उत्सव समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश भी देता है। रायपुर में आयोजित आंध्रा एसोसिएशन का मकर सं ांति समारोह इसी भावना का सशक्त और प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आया।

समारोह का आयोजन और शुभारंभ

श्री बालाजी विद्या मंदिर, सेक्टर-2, देवेंद्र नगर, रायपुर में आंध्रा एसोसिएशन, रायपुर द्वारा भव्य मकर संक्रांति समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री रामेन डेका (छत्तीसगढ़) के करकमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। समारोह में श्रीमती संध्या राज ने मकर संक्रांति के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व बताया, जो नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और छात्र सहभागिता

कार्यक्रम की सांस्कृतिक श्रृंखला का शुभारंभ गणेश स्तुति नृत्य से हुआ, जिसे कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा कु. टी. हासिनी ने अत्यंत भावपूर्ण और शास्त्रीय शैली में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात श्री वेतुरी नागेश एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत संक्रांति गीतों ने पूरे परिसर को लोक-संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया। स्वागत नृत्य में कक्षा दूसरी एवं छठवीं के छात्र-छात्राओं की सहभागिता ने दर्शकों का मन जीत लिया और यह स्पष्ट किया कि विद्यालय में सांस्कृतिक शिक्षा को भी समान महत्व दिया जाता है।

मुख्य आकर्षण

सुरों की अविस्मरणीय संध्या-समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण इंडियन आइडल से चर्चित कलाकार तथा इसी विद्यालय की पूर्व छात्राएँ बी. शिरीषा और बी. सौजन्या की सुरमयी प्रस्तुति रही। दोनों कलाकारों ने हिन्दी और तेलुगु गीतों की मनोहारी प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। शिरीषा द्वारा गाए गए लोकप्रिय हिन्दी गीत पर कक्षा नवमीं एवं ग्यारहवीं की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आकर्षक नृत्य ने कार्यक्रम में चार चाँद लगा दिए। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन करते नजर आए।

समाज की भूमिका और समापन

इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री जी. स्वामी ने आंध्रा समाज द्वारा किए गए शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज की एकता और सक्रिय सहभागिता को इसकी सबसे बड़ी शक्ति बताया। समारोह में समाज के बड़ी संख्या में लोग, विद्यालय की प्राचार्या, उपप्राचार्या, शिक्षकगण, छात्रवृंद एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अभ्यागतों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मनमोहक आतिशबाजी और रात्रि भोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह आयोजन न केवल मकर संक्रांति का उत्सव था, बल्कि सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सहभागिता और भावनात्मक जुड़ाव का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा।

सूरजपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विद्यार्थियों से सीधा संवाद

अरुणोदय कोचिंग बना वंचित युवाओं की सफलता की मिसाल...

डीएमएफ फंड से संचालित अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद किया। नि:शुल्क शासकीय कोचिंग से पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे व शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता। शिक्षा, पारदर्शिता और समान अवसरों पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर प्रवास के दौरान डीएमएफ फंड से स्थापित अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण कर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी, शैक्षणिक अनुभव और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली तथा संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को नजदीक से देखा। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अरुणोदय एक पूर्णत: शासकीय एवं नि:शुल्क कोचिंग व्यवस्था है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेषज्ञ मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और अकादमिक सहयोग बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अरुणोदय कोचिंग से प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों ने पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। इन उपलब्धियों ने न केवल विद्यार्थियों के जीवन की दिशा बदली है, बल्कि सूरजपुर जिले की शैक्षणिक पहचान को भी सशक्त किया है। विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह परिणाम सुदृढ़ शैक्षणिक योजना, समर्पित शिक्षकों और प्रशासनिक सहयोग का प्रतिफल है। उन्होंने जिला प्रशासन को संस्थान की स्थापना, संचालन और प्रभावी प्रबंधन के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने डीएमएफ फंड की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह फंड खनन प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और वहां निवासरत लोगों के कल्याण के लिए प्रारंभ किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बुनियादी सुविधाओं में किए जा रहे निवेश से दूरस्थ और पिछड़े अंचलों में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका सशक्त उदाहरण है, जहां संसाधनों की समान उपलब्धता से युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल, दिल्ली की जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक विद्यार्थी वहां नि:शुल्क रहकर उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने रायपुर स्थित नालंदा परिसर की सुविधाओं का भी उल्लेख किया, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से समृद्ध अध्ययन व्यवस्था उपलब्ध है। नालंदा की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 34 स्थानों पर हाईटेक लाइब्रेरी निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सूरजपुर भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य शासन पीएससी परीक्षा को यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए सतत कार्य कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चे भी पीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर आगे बढ़ रहे हैं, जो शासन की पारदर्शी नीतियों और अवसरों की समान उपलब्धता का सकारात्मक परिणाम है। संवाद के दौरान छात्र देवेंद्र ने अद्यतन पुस्तकों की आवश्यकता का विषय रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपने स्वेच्छानुदान से आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर को निर्देशित किया। वहीं पीएससी की तैयारी कर रहीं छात्रा गीता सिंह के स्वास्थ्य संतुलन संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने अपनी दिनचर्या साझा करते हुए समय पर उठने, नियमित योग, अपने इष्ट देव का स्मरण और समय पर भोजन करने की सलाह दी। अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने पंच, सरपंच, विधायक और सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक के जीवन सफर के अनुभव साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें, स्पष्ट लक्ष्य तय करें, बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम से जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को देश का भविष्य बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

लता मंगेशकर पुण्यतिथि विशेष- पुनर्जन्म पर उनका बयान, संघर्षों से भरा जीवन और अमर सुरों की विरासत...

स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उनका एक पुराना इंटरव्यू फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पुनर्जन्म को लेकर अपनी निजी और भावनात्मक राय रखी थी। यह बयान उनके सादगीपूर्ण, अनुशासित और त्याग से भरे जीवन की एक झलक भी देता है।

6 फरवरी भारत के सांस्कृतिक इतिहास की एक भावुक तारीख है। इसी दिन वर्ष 2022 में भारत की सबसे मधुर और सम्मानित आवाज़ों में से एक, लता मंगेशकर, 92 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गई थीं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हेमा मंगेशकर के रूप में जन्मी लता जी ने बहुत कम उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक जाने-माने रंगमंच कलाकार और गायक थे, जिनसे उन्हें संगीत की पहली शिक्षा मिली। बाल्यावस्था से ही सुरों से जुड़ाव रखने वाली लता मंगेशकर ने भारतीय फिल्म संगीत को न केवल नई ऊँचाइयाँ दीं, बल्कि अपनी आवाज़ से कई पीढ़ियों की भावनाओं को स्वर दिया।

लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर इन दिनों उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषय पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, हम हिंदू हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर पुनर्जन्म वास्तव में होता है तो मैं चाहूँगी कि मेरा पुनर्जन्म न हो। और अगर भगवान मुझे दूसरा जीवन दें, तो वह भारत में, महाराष्ट्र में, एक छोटे से घर में हो और मैं लड़के के रूप में जन्म लूँ। उनका यह बयान कई लोगों को चौंका गया, क्योंकि आमतौर पर लोग उनके जीवन को सफलता और सम्मान से भरा मानते हैं, जबकि इस कथन में उनके भीतर छिपे संघर्षों की झलक मिलती है।

लता मंगेशकर ने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बहुत कम बात की, लेकिन उनके करीबी और संगीत जगत से जुड़े लोग जानते हैं कि उनका सफर आसान नहीं था। पिता के निधन के बाद, जब वह बहुत छोटी थीं, तब परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उस दौर में एक युवा लड़की के लिए फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। कठिन परिश्रम, आत्मअनुशासन और आत्मसम्मान उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गए। उन्होंने कभी दिखावे या चकाचौंध भरी जिंदगी को नहीं अपनाया और हमेशा सादगी में विश्वास रखा।

गीतकार और कवि जावेद अख्तर के साथ एक अन्य इंटरव्यू में भी लता मंगेशकर ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर उन्हें दोबारा जन्म मिला भी, तो वह लता मंगेशकर बनकर जन्म नहीं लेना चाहेंगी। जब जावेद अख्तर ने उनसे इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, उन्हें केवल वही जानती हैं। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि अपार प्रसिद्धि और सम्मान के पीछे एक ऐसा जीवन भी था, जो निरंतर संघर्ष, त्याग और आत्मसंयम से भरा हुआ था।

संगीत को समर्पित संपूर्ण जीवन

लता मंगेशकर ने कभी विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन संगीत तथा परिवार की जिम्मेदारियों को समर्पित कर दिया। उन्होंने दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहते हुए एक सख्त और अनुशासित जीवन जिया। उनकी दिनचर्या, रियाज़ और काम के प्रति समर्पण की मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने कभी विवादों को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपनी आवाज़ की गरिमा बनाए रखी। यही कारण है कि संगीत जगत में उन्हें केवल एक गायिका नहीं, बल्कि एक संस्था के रूप में देखा जाता है।

पहला गीत, ऐतिहासिक ब्रेक और आखिरी आवाज़

लता मंगेशकर ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म कीर्ती हसाल से की थी, जिसमें उन्होंने गीत 'नाचू या गड़े, खेलो सारी मणि हौस भारी' गाया। हालांकि उन्हें असली पहचान 1949 में आई फिल्म महल के गीत 'आयेगा आने वाला' से मिली, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट गीत दिए और भारतीय संगीत पर अमिट छाप छोड़ी। उनके करियर का अंतिम गीत 2019 में रिकॉर्ड किया गया था, जब उन्होंने भारतीय सेना के लिए 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की' गाना गाया। यह गीत देशभक्ति और समर्पण की भावना से ओतप्रोत था।

अपने पांच दशकों से अधिक लंबे करियर में लता मंगेशकर ने 20 से अधिक भाषाओं में 30 हजार से ज्यादा गीत गाए। उन्हें भारत रत्न, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें न केवल उनके अमर गीतों के लिए, बल्कि उस जीवन के लिए भी याद करता है, जो उन्होंने चुपचाप, सादगी और अनुशासन के साथ जिया। लता मंगेशकर आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों तक भारतीय संस्कृति और भावनाओं की पहचान बनी रहेगी।

किसान विकास पत्र (KVP)- सुरक्षित निवेश, तय रिटर्न और पूंजी दोगुनी करने का भरोसेमंद विकल्प हो सकता है ...

Kisan Vikas Patra भारत सरकार की एक लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसे 1988 में दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जो बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। वर्तमान में इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 115 महीने (लगभग 9 वर्ष 7 माह) है, जिसके बाद निवेश की गई राशि लगभग दोगुनी हो जाती है। ब्याज दर सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही तय की जाती है और यह चक्रवृद्धि आधार पर लागू होती है।

योजना की प्रमुख जानकारी

किसान विकास पत्र में न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है — चाहे वह किसान हो या अन्य पेशे से जुड़ा व्यक्ति। इसमें सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट तथा नाबालिग के नाम पर भी निवेश किया जा सकता है (अभिभावक के माध्यम से)। सरकारी योजना होने के कारण इसमें पूंजी की सुरक्षा का भरोसा रहता है।

इस योजना में निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी हर वर्ष का ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और अगले वर्ष उसी पर ब्याज मिलता है। इसी वजह से तय अवधि पूरी होने पर राशि दोगुनी हो जाती है।

किसान विकास पत्र के फायदे

1. पूंजी की सुरक्षा- यह केंद्र सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए निवेश सुरक्षित माना जाता है।
2. तय और स्थिर रिटर्न-बाजार जोखिम से मुक्त, पूर्व निर्धारित अवधि में राशि दोगुनी।
3. कोई अधिकतम सीमा नहीं- बड़ी राशि निवेश करने वालों के लिए भी उपयुक्त।
4. ट्रांसफर सुविधा- KVP को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर किया जा सकता है।
5. आसान प्रक्रिया- डाकघर या अधिकृत बैंक में सरल आवेदन प्रक्रिया के साथ निवेश संभव।
6. लोन सुविधा- कुछ शर्तों के तहत KVP प्रमाणपत्र को गिरवी रखकर ऋण भी लिया जा सकता है।

समय से पहले निकासी और नियम

KVP में 30 महीने की लॉक-इन अवधि होती है। यानी निवेश के कम से कम 2 वर्ष 6 महीने बाद ही समय से पहले निकासी संभव है। विशेष परिस्थितियों जैसे निवेशक की मृत्यु या अदालत के आदेश पर समयपूर्व भुगतान किया जा सकता है।

टैक्स से जुड़े नियम

इस योजना में धारा 80ष्ट के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। प्राप्त ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है और इसे निवेशक की वार्षिक आय में जोड़ा जाता है। हालांकि, मैच्योरिटी पर ञ्जष्ठस् नहीं काटा जाता, जिससे अंतिम भुगतान पूरा प्राप्त होता है।

किसके लिए उपयुक्त?

यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो—

- कम जोखिम चाहते हैं
- लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं
- निश्चित रिटर्न पसंद करते हैं
- बाजार की अस्थिरता से बचना चाहते हैं

कुल मिलाकर, किसान विकास पत्र एक भरोसेमंद, सरल और सुरक्षित निवेश विकल्प है, जो अनुशासित बचत और पूंजी वृद्धि दोनों का संतुलित अवसर प्रदान करता है। यदि आपका लक्ष्य लंबी अवधि में सुरक्षित तरीके से राशि दोगुनी करना है, तो यह योजना आपके निवेश पोर्टफोलियो का स्थिर हिस्सा बन सकती है।

टी-20, विश्व कप 2026 में भारत का विश्वविजयी अभियान 16 लगातार जीत के साथ रचा नया इतिहास...

टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वह कर दिखाया है, जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल था। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अब तक 27 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, लेकिन 15 तारीख को खेला गया भारत-पाकिस्तान का मुकाबला इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप स्टेज के 27वें मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर न केवल एक बड़ी जीत दर्ज की, बल्कि आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार 16वीं जीत हासिल कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

19 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, भारत बना नंबर एक

आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के नाम था। कंगारू टीम ने 2006 से 2007 के बीच लगातार 15 मैच जीतकर यह कीर्तिमान बनाया था। उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा विश्व क्रिकेट पर साफ नजर आता था और यह रिकॉर्ड अटूट माना जा रहा था। लेकिन अब भारत ने 2024 से 2026 के बीच लगातार 16 मैच जीतकर उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। रिकॉर्ड्स की सूची पर नजर डालें तो 15 और 14 जीत का सिलसिला भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है, जबकि 2012 से 2014 के बीच भारत ने 12 लगातार मैच जीते थे। किंतु वर्तमान भारतीय टीम ने जिस निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया है, उसने इस उपलब्धि को विशेष बना दिया है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि टीम की मानसिक दृढ़ता, सामूहिक रणनीति और दबाव में संयम का प्रमाण है।

पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत, विश्व कप में 11वीं लगातार सफलता

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला केवल एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों की भावनाओं से जुड़ा आयोजन होता है। टी20 विश्व कप 2026 का यह हाई-वोल्टेज मैच भी इसी रोमांच का प्रतीक रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 175 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 118 रनों पर सिमट गई।

यह टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इसके साथ ही भारत ने विश्व कप में लगातार 11वीं जीत दर्ज की। दिलचस्प तथ्य यह है कि इस सूची में दक्षिण अफ्रीका 9 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत अब नए मानक स्थापित कर चुका है।

ईशान किशन की विस्फोटक पारी बनी जीत की धुरी

इस मुकाबले के नायक रहे भारतीय ओपनर ईशान किशन। उन्होंने मात्र 40 गेंदों पर 77 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 10 चौके

और 3 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, टाइमिंग और आक्रामकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। उन्होंने शुरुआती ओवरों से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और रनगति को स्थिर बनाए रखा।

केवल बल्लेबाजी ही नहीं, भारतीय गेंदबाजों ने भी अनुशासित प्रदर्शन किया। दोनों टीमों ने चार-चार स्पिनरों को अंतिम एकादश में शामिल किया था, लेकिन भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ और विविधता के दम पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मध्य ओवरों में लगातार विकेट गिरने से पाकिस्तान की पारी संभल नहीं सकी।

टीम संतुलन और रणनीति की जीत

भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे संतुलित टीम संयोजन बड़ी वजह रहा है। युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा और अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव–दोनों का समन्वय टीम को मजबूती देता है। बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में फुर्ती ने भारत को हर विभाग में बढ़त दिलाई है।

कोचिंग स्टाफ की रणनीतिक तैयारी और परिस्थितियों के अनुसार टीम चयन ने भी अहम भूमिका निभाई है। अलग-अलग पिचों पर अलग योजनाएं बनाना और विपक्षी टीम की कमजोरियों पर सटीक वार करना, यही इस भारतीय टीम की पहचान बन चुकी है।

विश्व क्रिकेट में भारत का बढ़ता प्रभाव

लगातार 16 जीत का यह सिलसिला केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट इस समय स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। विश्व क्रिकेट के दिग्गज भी इस प्रदर्शन से प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी लंबी जीत श्रृंखला को तोड़ना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए निरंतर फिटनेस, मानसिक मजबूती और रणनीतिक स्पष्टता जरूरी होती है।

भारतीय टीम का यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। यह बताता है कि अनुशासन, तैयारी और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

आगे की राह और उम्मीदें

टी20 विश्व कप 2026 अभी अपने निर्णायक चरणों की ओर बढ़ रहा है। भारत की यह शानदार लय यदि बरकरार रहती है, तो खिताब जीतने की उसकी संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हर मैच नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म और आत्मविश्वास को देखते हुए टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

फिलहाल, पूरे क्रिकेट जगत की नजरें भारत के अगले मुकाबले पर टिकी हैं। क्या यह विजय रथ और आगे बढ़ेगा? क्या टीम इंडिया अपने इस ऐतिहासिक अभियान को ट्रॉफी के साथ मुकम्मल करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि 16 लगातार जीत का यह अध्याय भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा।

जन सुविधा शिविरों से बदल रही सुकमा की तस्वीर

शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सुकमा जिले में व्यापक स्तर पर जन सुविधा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में 4 फरवरी से प्रारंभ यह अभियान प्रशासन की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अब तक कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा विकासखंड के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में 23 शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 40 ग्रामों के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ ही उन्हें पात्रतानुसार लाभान्वित किया गया है। यह जन-अभियान 28 फरवरी तक सतत रूप से संचालित होगा। शिविरों में जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी समीक्षा कर रहे हैं। पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जन सुविधा शिविरों में ग्रामीणों को एक ही स्थान पर आधार अपडेट एवं नवीन पंजीयन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, आभा आईडी जनरेशन, वय वंदन योजना कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, किसान पंजीयन एवं उसका अद्यतन, ई-केवाईसी सहित विभिन्न हितग्राहीमूलक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस एकीकृत व्यवस्था से ग्रामीणों को शासकीय कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब तक कुल 9,473 ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

रायपुर नगर निगम की बागडोर संभालती महापौर मीनल चौबे

विकास, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता की नई दिशा...

छत्तीसगढ़ की राजधानी का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र होने के नाते रायपुर नगर निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संस्था का नेतृत्व करते हुए महापौर मीनल चौबे ने शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जल प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में कई सक्रिय पहलें की हैं। उनके कार्यकाल को प्रशासनिक सक्रियता, जनसंवाद और योजनाबद्ध विकास के संदर्भ में देखा जा रहा है।

शहरी आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की पहल

महापौर के रूप में मीनल चौबे ने सड़कों के उन्नयन, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर विशेष बल दिया है। शहर की बढ़ती जनसंख्या और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए वार्ड स्तर पर सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण कार्यों को प्राथमिकता दी गई। कई प्रमुख मार्गों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गईं, जिससे ऊर्जा की बचत के साथ सुरक्षा भी बढ़ी।

नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण और पुराने भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य भी उनके कार्यकाल में गति पकड़ता दिखा। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है।

स्वच्छता अभियान और कचरा प्रबंधन

स्वच्छता के क्षेत्र में महापौर ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। शहर में सूखा और गीला कचरा पृथक्करण की जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए गए। कई वार्डों में स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के उद्देश्य से विशेष मॉनिटरिंग टीमें गठित की गईं।

कचरा प्रबंधन संयंत्रों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा और नागरिकों से सीधे फीडबैक लेने की पहल ने व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया है। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और शासकीय कार्यालयों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए जुर्माना और जागरूकता—दोनों रणनीतियाँ अपनाई गईं।

जल आपूर्ति और जल संरक्षण

गर्मी के मौसम में जल संकट की समस्या को ध्यान में रखते हुए टैंकर आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार और लीकेज सुधार के कार्य किए गए। वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए निगम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को सक्रिय रखकर नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण की दिशा में प्रयास किए गए।

डिजिटल पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार

नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाया गया। कर भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से नागरिकों को सुविधा मिली है।

महापौर नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से विभागीय कार्यों की प्रगति का आकलन करती रही हैं। इससे प्रशासनिक जवाबदेही को बल मिला है। कई वार्डों में जनचौपाल आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सीधे सुनी गईं, जो स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बना।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक पहल

एक महिला महापौर के रूप में मीनल चौबे ने महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने और उन्हें नगर निगम की योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया। स्वच्छता, पोषण और सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़े अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया।

साथ ही, गरीब और जरूरतमंद वर्गों के लिए शिविरों का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश को मजबूती मिली।

चुनौतियाँ और अपेक्षाएँ

हालांकि नगर निगम के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। तेजी से फैलता शहरीकरण, ट्रैफिक दबाव, जल निकासी की पुरानी व्यवस्था और सीमित वित्तीय संसाधन प्रशासन के लिए निरंतर परीक्षा बने हुए हैं। नागरिकों की अपेक्षाएँ भी समय के साथ बढ़ी हैं, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।

इन परिस्थितियों में महापौर की भूमिका केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं, बल्कि उनके धरातल पर परिणाम सुनिश्चित करने तक विस्तृत हो जाती है।

रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे के कार्यकाल को शहर के समग्र विकास की दिशा में एक सक्रिय चरण के रूप में देखा जा सकता है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता सुधार, जल प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं और नागरिक सहभागिता को प्राथमिकता देने के प्रयास उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

आगे की राह में स्थायी विकास, पर्यावरण संतुलन और पारदर्शी शासन जैसे मुद्दे केंद्रीय रहेंगे। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर जनसंवाद बना रहता है, तो राजधानी के रूप में ऋइुद्धश्चह्वह्न का शहरी विकास और अधिक सुदृढ़ और संतुलित रूप ले सकता है।

स्कूली बच्चों की प्रस्तुति से प्रभावित हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह , ताली बजाकर बढ़ाया उत्साह

संभाग स्तरीय बस्तर पण्डुम 2026 के समापन समारोह में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और ताली बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री के स्वागत में जगदलपुर के हजारों स्कूली बच्चों ने ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बच्चों की भावपूर्ण और अनुशासित प्रस्तुति देखकर श्री अमित शाह भी भावविभोर हो उठे और उन्होंने बच्चों को ताली बजाकर प्रोत्साहित किया।

बस्तर पण्डुम समापन समारोह में बच्चों की कला को मिला केंद्रीय गृहमंत्री का सम्मान- कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा *मलखंभ प्रदर्शन* भी किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने बच्चों की कला, अनुशासन एवं आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने भी बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

उल्लेखनीय है कि ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत को हिंदी एवं हल्बी बोली में रचा गया है। इसमें बस्तर की बादल अकादमी के कलाकारों ने अपनी आवाज और संगीत का योगदान दिया है। दायरा बैंड द्वारा इस गीत को आधुनिक संगीत के साथ नया स्वरूप प्रदान किया गया है, जिससे यह गीत युवाओं और बच्चों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हो रहा है।

होलाष्टक 2026-24 फरवरी से शुरू होंगे अशुभ आठ दिन, जानिए क्यों टाले जाते हैं शुभ कार्य और क्या है धार्मिक महत्व...

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से हर वर्ष की तरह इस बार भी होलाष्टक की शुरुआत होने जा रही है। साल 2026 में 24 फरवरी, मंगलवार की सुबह 7 बजकर 02 मिनट से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और इसी के साथ होलाष्टक लग जाएंगे। यह अवधि 3 मार्च को होलिका दहन के दिन समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार होलाष्टक होलिका दहन से ठीक आठ दिन पहले शुरू होते हैं और इन आठ दिनों को विशेष सावधानी का समय माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दौरान ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं, जिससे मांगलिक कार्यों में बाधा या विघ्न की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय आरंभ, मकान या वाहन की खरीद जैसे शुभ कार्य इन दिनों में वर्जित माने गए हैं।

क्या है होलाष्टक का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व

हिंदू धर्म में होली का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली से पूर्व के आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। 'होलाष्टक' शब्द 'होली' और 'अष्टक' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है होली से पहले के आठ दिन। धार्मिक दृष्टि से यह समय तप, संयम और भक्ति का काल माना जाता है। भले ही मांगलिक कार्यों की मनाही हो, लेकिन देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना, जप-तप और दान-पुण्य के लिए यह अवधि अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। कई श्रद्धालु इस दौरान विशेष रूप से भगवान विष्णु और अपने इष्टदेव की आराधना करते हैं ताकि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सके।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन आठ दिनों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु जैसे प्रमुख ग्रहों की स्थिति को संवेदनशील माना जाता है। यह मान्यता है कि ग्रहों की उग्रता के कारण नए कार्यों की शुरुआत स्थिर फल नहीं दे पाती। इसलिए परंपरा के अनुसार परिवारों में बड़े-बुजुर्ग इन दिनों में कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करने से रोकते हैं। हालांकि नियमित पूजा, हवन, सत्संग और आध्यात्मिक साधना को पूर्ण रूप से शुभ माना गया है।

प्रह्लाद और होलिका की कथा से जुड़ा है होलाष्टक

होलाष्टक के पीछे पौराणिक कथा भी जुड़ी है, जिसका संबंध राजा हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र भक्त प्रह्लाद और बहन होलिका से है। मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप चाहते थे कि उनका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे और उन्हें ईश्वर माने। जब प्रह्लाद ने ऐसा करने से इंकार कर दिया, तो राजा ने उसे अनेक यातनाएं दीं। कहा जाता है कि आठ दिनों तक प्रह्लाद को तरह-तरह से कष्ट दिए गए, लेकिन वह हर बार भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित रहे।

अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, की गोद में प्रह्लाद को बैठाकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया। किंतु ईश्वर की कृपा से होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई और भक्त प्रह्लाद सुरक्षित बाहर आ गए। यह घटना फाल्गुन पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हुई मानी जाती है, जिसे आज होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। प्रह्लाद को दिए गए उन्हीं आठ दिनों के कष्टों की स्मृति में होलाष्टक की परंपरा मानी जाती है।

सामाजिक परंपराएं और मान्यताएं

होलाष्टक से जुड़ी कुछ सामाजिक परंपराएं भी प्रचलित हैं। कई स्थानों पर नई विवाहित बेटियों को विवाह के बाद पहली होली ससुराल में न मनाने की सलाह दी जाती है। यह परंपरा भी होलाष्टक और होली से जुड़ी मान्यताओं का हिस्सा मानी जाती है। हालांकि आधुनिक समय में कई परिवार अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार इन परंपराओं का पालन करते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि होलाष्टक केवल निषेध का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी है। यह आठ दिन हमें यह संदेश देते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति, धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार भक्त प्रह्लाद ने कठिन यातनाओं के बावजूद अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उसी प्रकार जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी आस्था और साहस के साथ करना चाहिए।

इस प्रकार 24 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने वाले होलाष्टक केवल परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, ज्योतिष और पौराणिक इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवधि है, जो होली के पावन पर्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को और भी गहराई प्रदान करती है।

विराट आस्था का प्रतीक- मोतिहारी के कैथवलिया में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित...

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के कैथवलिया-बहुअरवा गांव में स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना भारतीय धार्मिक और स्थापत्य परंपरा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। 17 जनवरी 2026 को इसकी विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसके साथ यह स्थल राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि शिल्पकला, अभियांत्रिकी और दीर्घकालिक संकल्प का उत्कृष्ट उदाहरण भी है।

राखी श्रीवास्तव

अद्वितीय आयाम और निर्माण कौशल

इस शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट तथा परिधि भी 33 फीट है, जबकि इसका कुल वजन लगभग 210 टन (2,10,000 किलोग्राम) है। इसे 38 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है, जिससे आधार से इसकी कुल ऊंचाई लगभग 55-56 फीट तक पहुंच जाती है। इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर (मोनोलिथिक संरचना) को तराशकर तैयार किया गया। इस भव्य शिल्प को आकार देने में लगभग 10 वर्षों का समय लगा, जो इसकी जटिलता और कलात्मक परिशुद्धता को दर्शाता है।

विशेष बात यह है कि यह एक 'सहस्त्रलिंगम' है, जिस पर 1,008 छोटे-छोटे शिवलिंग बारीकी से उकेरे गए हैं। यह स्वरूप शैव परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। श्रद्धालु मंदिर की पांचवीं मंजिल से एस्केलेटर के माध्यम से ऊपर पहुंचकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकेंगे, जिससे दर्शन और पूजा का अनुभव अत्यंत विशिष्ट हो जाता है।

विराट रामायण मंदिर- वैश्विक स्थापत्य की झलक

विराट रामायण मंदिर स्वयं में विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है। इसकी प्रस्तावित लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। परिसर में कुल 22 मंदिर और 18 शिखर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट निर्धारित है, जो कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट (लगभग 215 फीट) से भी अधिक है। मंदिर का स्थापत्य भारतीय और दक्षिण-पूर्व एशियाई शैली का संगम है। इसका डिजाइन अंगकोर वाट, रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर तथा मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित बताया जाता है।

मंदिर के मुख्य हॉल में एक साथ लगभग 20,000 श्रद्धालु बैठ सकेंगे। यहां भगवान राम, सीता, लव-कुश और महर्षि वाल्मीकि सहित अन्य प्रमुख हिंदू देवी-देवताओं के लिए अलग-अलग गर्भगृह प्रस्तावित हैं। यह समावेशी संरचना रामायण काल की सांस्कृतिक विरासत को साकार रूप देने का प्रयास है।

दर्शन व्यवस्था और भविष्य की योजना

मंदिर सामान्यत: सुबह 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक खुला रहता है, हालांकि विशेष पर्वों या निर्माण कार्यों के दौरान समय में परिवर्तन संभव है। यह स्थल पटना से लगभग 120 किलोमीटर और वैशाली से 60 किलोमीटर की दूरी पर, केसरिया-चकिया मार्ग पर स्थित है, जिससे सड़क मार्ग से पहुंचना अपेक्षाकृत सुगम है।

यद्यपि शिवलिंग की स्थापना पूर्ण हो चुकी है, संपूर्ण मंदिर निर्माण कार्य को 2028-2030 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्ण होने पर यह परिसर धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक अध्ययन और स्थापत्य अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इस प्रकार, कैथवलिया का यह शिवलिंग केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक निर्माण क्षमता का संगम भी है।

Baldeo Furnitech
Pvt. Ltd

Furniture
that Feels Like
Home

+91-7597333333
baldeo_furnitech

BALDEO FURNITECH,
BESIDE SAHANI PARK,
RING ROAD NO.1, RAIPUR

छत्तीसगढ़ संवाद आर.ओ.-13670/267

प्रगतिशील युवा
विकसित छत्तीसगढ़

खेल प्रोत्साहन योजना लागू, ओलंपिक विजेताओं के लिए **₹1-3 करोड़** का पुरस्कार और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल ढांचे का विकास

सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, लगभग **32,000 पदों** पर भर्ती

नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को **7.96 एकड़** भूमि आवंटित

160 आईटीआई को मॉडल संस्थान में बदलने हेतु **₹484 करोड़** स्वीकृत

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए **उद्यम क्रांति** योजना

34 नगरीय निकायों में "नॉलेज बेस्ड सोसाइटी" **हेतु लाइट हाउस** निर्माण की पहल

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprog.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री